they do not give a complete picture inasmuchas the complexity of the cases has also risen with time. In 1957, the law was amended to enable the Director of Enforcement to adjudicate cases in lieu of taking recourse to prosecution in the courts of law as adjudication was certainly a speedier and more expedient method of settling these cases. Since we did not expect a large number of cases to arise, the power of adjudication was conferred only on the Director himself and on no other officer in the entire hierarchy. Our experience, however, has shown that the volume of work involved in the numerous cases and initiating adjudication proceedings necessitates that the Directorate of Enforcement should be assisted from officers of Customs, Central Excise, Police and other Departments of the Government. We are, therefore, taking powers to entrust any or all the functions of the Director of Enforcement to officers of the above-mentioned Departments.

The law, as it stands today, does not empower the officers of the Enforcement Directorate to arrest offenders, to stop and search conveyances, to search premises, to summon persons and record their evidence. This seriously handicaps the Directorate in the discharge of its duties. We are, therefore, proposing to give to these officers the above-mentioned powers which are now being enjoyed by Customs officials. It is hoped that with these added powers, the Directorate of Enforcement will be able to investigate violations of law more effectively.

Madam, the Bill received extensive support in the Lok Sabha. I am quite certain that this House too will be generous in its support to the Government in our move to bring these offenders to book.

During the course of investigation, the Directorate of Enforcement come across documents and information which, though not directly related to foreign exchange, are of considerable interest to other Departments of the Government. We are empowering them to communicate the relevant information to the concerned duly authorised officers.

The Appellate Board, which hears appeals from the decisions of the Director of Enforcement, at present consists of one Chairman and one more member. There can be disagreement in the views taken by the members and the present composition of the Board does not take care of these contingencies. The composition of the Appellate Board is, therefore, being altered so as to have three members in all, including the Chairman. The law, as it stands today, does not provide for an appeal against the decisions of the Board and we are now proposing to provide for an appeal to the High Court on points of law only.

THE DEPUTY CHAIRMAN: You may continue later. It is now 4 o'clock. We will now take up the other business.

---

4 P.M.

MOTION *RE* REPORT OF THE COMMISSION OF INQUIRY ON CERTAIN ALLEGATIONS AGAINST FORMER CHIEF MINISTER OF PUNJAB

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Chordia. You will have fifteen minutes.

SHRI V. M. CHORDIA (Madhya Pradesh): Twenty minutes, Madam.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Fifteen minutes, and I hope all those who participate in this will focus their comments on the Report of the Commission of Enquiry.

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : उपसभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"पंजाब के भूतपूर्व मुख्य मंत्री सरदार प्रताप सिंह कैरों के विरुद्ध लगाए गए कतिपय

[श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया]

आरोपों की जांच करने तथा उनके सम्बन्ध में प्रतिवेदन देने के लिए गृह-कार्य मंत्रालय की अधिसूचना एस० ओ० न० ३१०६, दिनाक १ नवम्बर, १९६३ के अधीन, श्री एस० आर० दास की अध्यक्षता मे गठित जांच आयोग के प्रतिवेदन पर, जो ७ सितम्बर, १९६४ को राज्य सभा की मेज पर रखा गया था, विचार किया जाए ।"

उपसभापति महोदया, पंजाब के भूत-पूर्व मूख्य मत्री श्री प्रताप सिह कैरों के बारे मे जो भ्रष्टाचार, कुनबापरस्ती, अव्यवस्था और जितनी भी अवैधानिकता हो सकती थीं, उन सब के बारे मे उन पर जो आरोप लगाए गए उनकी जाच करने के लिए हमारी सरकार ने एक आयोग की नियुक्ति की । यह कदम एक ऐतिहासिक कदम है क्योंकि कई शिकायते हमारे मुख्य मंत्रियों के बारे मे होती रही, होती है, ये काफी अर्से से चल रहा था और इन मुख्य मंत्री के बारे मे जाच करने के लिए आयोग की नियुक्ति हुई फिर भी वे मुख्य मत्री बने रहे, तो ऐसी स्थिति मे यह एक ऐतिहासिक घटना के रूप में हमारे यहा हमेशा याद रहेगी ।

अगर हमारे सरदार प्रताप सिह कैरों के कारनामो को देखा जाय, तो मुझसे ज्यादा माननीय अब्दुल गनी साहब इसे जानते हैं, जो कि इसमे शूरू से आखीर तक रहे, सारे काम को आगे बढ़ाने मे रहे, प्रताप सिह कैरों को इस दशा मे लाने में रहे, मुख्यत: वह और उनके साथी—कई और भी इसमें उनके साथी है वे भी, बहुत धन्यवाद के पात्र हैं ।

यह हमारे सरदार प्रताप सिह कैरो काग्रेस के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं । सन् १९५२ ई० मे वह पंजाब के विकास मंत्री बने थे, सम्भवत. उसी समय से उन्होने सोचा कि सारे राष्ट्र के विकास को करने की अपेक्षा या खाली पंजाब के विकास को करने की अपेक्षा पहले स्वयं अपना विकास कर लें, फिर अपने कुटुम्बियों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए विकास कर ले, फिर अपने मित्रों का विकास कर लें और उसी विकास विभाग के पोर्टफोलियो को पूरा करने की दृष्टि से उन्होंने विकास विभाग मे काम प्रारम्भ किया और फिर बाद मे १९५६ ई० में वे मुख्य मंत्री पद पर आसीन हुए । तो जो पुरानी विकास करने की आदत थी वह बराबर चलती रही और सारा विकास अपने स्वयं की दृष्टि से, अपने कुटुम्बियों की दृष्टि से, अपने पुत्रों की दृष्टि से, अपने मित्रो की दृष्टि से और अपने आसपास की दृष्टि से—जिन्हे कि रिपोर्ट मे कैरों ट्राइब कहा गया है—उनसे जितना भी हो सका उतना करने का प्रयत्न किया । उन्होने अपने पद का दुरुपयोग भी किया और जो कुछ भी करना था वह सब किया, यह सारा इस रिपोर्ट मे अच्छी तरह से प्रकाशित है ।

उन पर जो आरोप लगाए गए वे आरोप अमृतसर कोआपरेटिव कोल्ड स्टोरेज के बारे में है, कैरों के ईंटों के भट्टे के बारे में है—ईंट के भट्टे को भी नही छोडा—प्रकाश सिनेमा और मुकुट हाउस के बारे में है, नेशनल मोटर्स के माध्यम से प्रीमियर आटोमोबाइल्स की एजेंसी और उसकी मार्फत अपने यहा जो गवर्नमेंट का ट्रांस्पोर्ट था उसमे फार्गो, डाज आदि मोटरो के विक्रय के बारे मे है, और नीलम सिनेमा, चंडीगढ़ पटियाला कैपिटल सिनेमा, पटियाला के कोल्ड स्टोरेज, लुधियाना के कोल्ड स्टोरेज, हिसार के इलाईट सिनेमा, नन्दन सिनेमा तथा पंजाब कोल्ड स्टोरेज, फरीदाबाद के नीलम सिनेमा के बारे में है। यह तो एक व्यापक यादी है ही, इसके अलावा और भी अन्य आरोपो की एक लम्बी चौड़ी फहरिश्त है । जैसे कि २५ हजार रुपया एक ही तारीख को बैंक मे जमा करना—जहां कही से भी आ गया हो—, संगरूर की जागीरदारी की जायदाद का मामला, हरिजनों को दी जाने वाली जमीन

के बारे में अपने रिश्तेदारों को पहुंचाया गया लाभ, अपने दामाद रनजीत सिंह को मदद करने के लिए सीड फार्म का घोटाला, खराब बीज को खरीदकर एक ही व्यापारी से एक ही कीमत पर ले लेना, वगैरह-वगैरह, ऐसे बहुत सारे आरोप हैं जिसे हमारे ये माननीय सदस्यों ने मेहनत करके, अपना प्रतिवेदन दे कर प्रकाशित किए। इनको बहुत मेहनत करनी पड़ी और इनको सब कुछ करना पड़ा और दास कमिशन ने उनकी जांच कर के जो रिमार्क दिया है वह तो रपोर्ट में है ही, इन सारी घटनाओं को दुहराकर मैं सदन का समय लेना नही चाहता।

तो ये सारी घटनाएं एक रोज में हो गई, ऐसी बात नहीं है। उपाध्यक्ष महोदया, ये क्रमशः हुईं, एक प्रासेस था वह क्रमशः चलता गया, एक कदम के बाद दूसरा कदम और दूसरे कदम के बाद तीसरा कदम बढ़ा और इस तरह से वह सारे कदम बढ़ाते गए। इसके बारे में विरोधी दल के लोगों ने कहा, लेकिन उनके अलावा सब से पहले हमारे प्रबोध चन्द्र जी ने, जो कि कांग्रेस के कार्यकर्त्ता हैं उन्होंने और अन्य लोगों ने कांग्रेस को हाई कमांड को सन् १९५८ में लिख कर भेजा कि आपके प्रताप सिंह कैरों के ये कारनामें हैं। उनकी जांच की गई और फिर हमारे श्री मन्नारायण अग्रवाल ने उसके बारे में जो लिखा वह मैं संक्षेप में प ढ़ कर सुना दू। उन्होंने लिखा :

"Certain improprieties were committed. While Sardar Pratap Singh may not have been personally aware of these, a person in his position must be deemed to be constructively responsible and there were certain procedural irregularities in administrative matters."

तो उन्होंने थोड़ा सा इशारा किया था। इंसान को इशारा काफी होता है मगर वह इंसान हो तो। मगर इंसान के अलावा सरकार को भी इस इशारे की गम्भीरता समझ में नहीं आई और इस के बाद उनकी गति और बढ़ती गई, गति इतनी बढ़ गई और उन्होंने पापों का भंडार इतना संगृहीत कर लिया कि इस के बाद फिर १९६० में प्रबोध चन्द्र जी ने हाई कमांड से कहा कि इन श्रीमान का काम सम्भालिए। मगर शायद कांग्रेस दल यह सोच रहा था कि अगर प्रताप सिंह कैरों वह नहीं होगा, तो हमारी कांग्रेस की लुटिया डूब जायगी या और कारण होंगे। तो यहां पर हमारे प्रधान मंत्री जी ने भी और गृह मंत्री जी ने भी कहा कि इन आरोपों में तथ्य नहीं है, आरोपों की जांच हो रही है, तथ्यहीन आरोप हैं। मगर हमारे ही श्री अब्दुल ग़नी और कई कांग्रेस के सदस्य जो कि उनके साथ थे कहते रहे कि ऐसा नहीं है क्योंकि वे उनसे पीड़ित थे, वे जानते थे कि वहां की क्या स्थिति है और उसी के परिणामस्वरूप उन्होंने सारा प्रतिवेदन किया, सारा मसला उठाया। मगर हमारे प्रपाप सिंह कैरों को समझ नहीं आई इतना ही नहीं वहां पर अख़बारों में भी खूब खूब प्रकाशन किया, हिन्दुस्तान टाइम्स ने, ट्रिब्यून ने, बाम्बे क्रानिकिल ने जनता के मत को प्रकट किया। पर इस सब का असर नहीं हुआ। असर तो उस पर हो जिसके ऊपर कुछ असर हो सके, जैसे कि चिकने घड़े पर पानी डालने का कुछ असर नहीं होता या जिस को शर्म नहीं हो उसको शर्म की बात कही जाय, तो शर्म लग नहीं सकती या कोई बिल्कुल ही, जैसा कि कहा जाता है, "नसर-गट" हो तो उसको कितना ही कहा जाय कुछ असर नहीं होता। तो विधान सभा में सारी चिल्ल पों हुई, संसद् में इसके बारे में आवाज़ उठाई गई, अख़बारों में इस के बारे में आवाज़ उठाई गई, प्रतिवेदन दिए गए, डेपुटेशंस मिले, मगर कुछ असर नहीं हुआ। फिर बाद में एक डेपुटेशन १९६३ ई० की १३ जुलाई को मिला, शनिवार के रोज़, तारीख भी और दिन भी ऐसा ढूंढा गया, शनिवार का दिन ढूंढा गया, उन दिन शनि की दशा कुछ सरदार साहब के ठीक न होगी या कुछ ऐसी बात होगी। उसके परिणाम स्वरूप आयोग की नियुक्ति हुई और आयोग

[श्री बिमलकुमार मन्नालालजी चोरडिया]

आयोग की नियुक्ति के बाद कार्यवाही शुरू हुई ।

अब, जाच आयोग ने ज्युरिसप्रुडेंस के उच्च सिद्धांत का पूरा पालन करते हुए बिल्कुल स्पष्ट कहा कि हम यह मान कर चलेंगे कि हमारे द्वारा कोई ऐसा आदमी नुकसान मे न पड़ जाय जो कि सचमुच में इननोसेंट हो, हम यह नहीं चाहते, और जब तक कि पूरे प्रमाणों के साथ यह प्रमाणित न हो जाय कि कोई व्यक्ति दोषी है तब तक हम उसको दोशी नहीं मानेंगे । ऐसे सिद्धांतों को मान कर कर के चला और उसके बाद जांच प्रारम्भ की । अब एक तरफ तो वह चीफ मिनिस्टर के पद पर विद्यमान रहे, दूसरी तरफ श्री अब्दुल गनी और उनके साथी अपनी ओर से प्रयत्न करते रहे, जब जस्टिस एस० आर० दास का जांच आयोग बैठा हुआ था तब पूरी का पूरा सत्ता सरदार कैरों के हाथ मे थी, वहां के चीफ सेक्रेटरी ने काफी एफेडेविट्स दिए इस बात के लिए कि प्रताप सिंह कैरों साहब बच जायं । तो पूरी सत्ता, पूरी शक्ति उन के पास रही, साम दाम दंड भेद इन चारो गुणो से सम्पन्न चीफ मिनिस्टर बने रहे और इन का उपयोग किया । तो एक तरफ वह मुख्य मंत्री पद पर रहे और दूसरी तरफ हम तुलना करते है और अगर काश्मीर को देखते है, तो बख्शी गुलाम मुहम्मद--जिन पर केवल भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, अभी वे प्रमाणित नही हुए, उसके पीछे ही--उन को तो जेल के सीखचों मे बन्द कर दिया और यहा पर प्रमाण हो चुका, सारी रिपोर्ट हो चुकी, सब कुछ हो चुका ? तो यह तो हमारे शासन की दुहरी नीति है, वह किन कारणों से क्या है कुछ समझ मे नही आता कि कही, तो बल्लम की जो नोक है वह बड़ी तेज हो जाती है और कही पर बिल्कुल काम नही करती, एक तरफ तो बख्शी गुलाम मुहम्मद को जेल की सीखचो मे बन्द कर दिया और दूसरी तरफ प्रताप सिह कैरों अभी भी मौज से मस्ती से चल रहे हैं, चाहे इस रिपोर्ट मे कुछ भी हो । इस दृष्टि से, जाच आयोग ने सारे अपने सिद्धातों का पालन करते हुए , उनके मुख्य मंत्री पद पर विद्यमान होते हुए भी, यह रिपोर्ट दी । हमारे सदस्यो ने, माननीय गनी साहब ने और उनके साथियो ने, अन्य लोगों ने जो प्रयत्न इस के लिए किया है वह प्रशंसनीय है, ऐसी स्थिति मे सचमुच मे इतना उद्योग करके, इतना काम किया जाय यह सम्भव नही है । इन सारी बातो के बावजूद, जो इस रिपोर्ट मे दिया हुआ है, मैं उसके खास हिस्से को पढ़कर सुना देना चाहता हू जिससे सदन का समय ज्यादा न लिया जाय .

"These notings it is contended clearly indicated how the Government machinery was being misused and how S. Partap Singh Kairon and/or his colleagues or the subordinate employees were functioning in giving undue favours to the sons and relatives of S. Partap Singh Kairon and fixed him with knowledge of what was happening.

The cumulative effect of what transpired at the trial of S. Harbhajan Singh, the allegations made in the charge sheets of 1958 and 1960 and the findings of the Congress High Command on that of 1958, the articles in the Press, the Assembly questions and S Partap Singh Kairon's own orders on files containing the notings by other Ministers, Deputy Ministers or the Government officials is undoubtedly significant and cannot be easily ignored"

फिर आगे यह बताया गया है :

"He should have realised that the allegations and insinuations thus made openly and persistently not only reflected on his own character and probity but were also bringing the Government of which he was the head into hatred, ridicule and contempt. Therefore, these allegations, irrespective of their correctness or truth should have put him on guard and should have induced

him to make discreet inquiry as to the truth or falsity of those allegations and whatever might have been the result of such inquiry he should have warned his sons, his colleagues and subordinate officials against the repetition of such misconduct. He failed to give any warning to anybody, for in his affidavit he says that if any misdeed of his sons had been brought to his notice he would have warned his sons which statement clearly means and implies that nothing had been brought to his notice and he had given no warning. The Commission is free to concede that a father cannot legally or morally prevent his sons from carrying on business but the exploitation of the influence of the father who happens to be the Chief Minister of the State cannot be permitted to be made a business of. Such exploitation cannot possibly be a legitimate business and the father's influence and powers cannot be permitted to be traded in."

लेकिन उनके लड़कों ने अपने पिता जी के पद का व्यापार करना प्रारम्भ कर दिया। इस तरह के कुछ और आरोप इसमें दिये गये हैं। आगे इसमें बताया है :

"Even assuming he personally had not lent a helping hand in relation to them, the least he could do was to give a stern warning, in private and if necessary publicly, to his sons, relatives, colleagues and subordinate officers against their alleged conduct even if such conduct had not been proved to be true."

फिर इसमें कहा गया है :

"But, as his own affidavit shows, he made no inquiry, gave no warning to anybody and took no step whatever to prevent its recurrence but let things drift in the way they had been going. . .".

अन्त में इसमे बताया गया है :

"He cannot now plead ignorance of facts. In view of his inaction in the face of the circumstances hereinbefore alluded to he must be held to have connived at the doings of his sons and relatives, his colleagues and the Government officers. This is the true position, as the Commission apprehends it. It will be for the authorities to consider and decide what consequences follow from such connivance."

इस तरह की तमाम बातें सारी रिपोर्ट में दी हुई हैं। जितने भी जघन्य पाप हो सकते हैं जिनकी कि कल्पना की जा सकती है वे समस्त पाप, अपवादस्वरूप कुछ को छोड़कर, वहां पर दोहराए गए और उसमें सरदार प्रताप सिंह कैरों कितनी सीमा तक जिम्मेदार हैं, इसकी रिपोर्ट दास कमीशन ने बड़ी मेहनत करके दी। अब उन्होंने यह शासन पर छोड़ दिया कि यह शासन पर निर्भर करता है उसकी नीति कैसी हो, किस तरह से उनको सजा दे, किस तरह से उनके खिलाफ कार्यवाही करें। तो उसके बारे में हमारी सरकार ने अभी तक कोई भी उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की। इतना ही नहीं, कुछ व्यक्ति विशेष ने, जिन्होंने पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट दी कि उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय, उस पर भी कोई ऐक्शन नहीं लिया था। हमारे होम मिनिस्टर साहब कह देते हैं हमने तो कृष्णस्वामी साहब को इन सब बातों की जांच पड़ताल के लिये अपाइन्ट कर दिया। हमारे होम मिनिस्टर यह भी कहते हैं पंजाब सरकार उनके खिलाफ कार्यवाही करेगी। पंजाब सरकार कहती है हमने इधर होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट दी है। फिर यहां ये कहते हैं हम कार्यवाही करने वाले हैं। न वहां पंजाब सरकार कुछ करती है और न यहां सेन्ट्रल गवर्नमेंट कुछ करती है। इन दोनों के झगड़े में हमारे सरदार प्रताप सिंह कैरों एण्ड कम्पनी ने जो धन संग्रह किया था उसका वह दुरुपयोग कर रहे थे, सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। इस दृष्टि से मैं निवेदन करूंगा कि क्या वह प्रिवेन्शन आफ करप्शन ऐक्ट जो हमारी सरकार द्वारा संसद से पास कराया गया, क्या वह इस

[श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरडिया]

मामले में लागू नही होता क्या उनकी किसी भी कार्यवाही के खिलाफ यह लागू नहीं किया गया है या उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की ही नहीं जा सकती ? इसके बारे में सरकार जवाब दे ।

आफिसरों की स्थिति के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार के सामने कुछ आफिसर तो ऐसे आयेंगे जिन्होंने सचमुच में स्वयं उसका लाभ भी उठाया और उनकी मदद भी की । ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये । मगर जिन आफिसरों ने केवल दबाव में आने के कारण, सरदार प्रताप सिंह कैरों के चीफ मिनिस्टर होने के परिणामस्वरूप मदद की और जो मदद देने के लिये बाध्य किये गये थे क्योंकि अगर मदद नहीं देते, तो नौकरी से संभवतः बरखास्त कर दिये जाते, तो ऐसे लोगों के मामले के बारे में विचार किया जाना अत्यंत आवश्यक है । इस दृष्टि से हमें ऐसी भी व्यवस्था करनी चाहिये कि जिससे अन्य स्थानों में चीफ मिनिस्टर्स ऐसा काम नहीं करें कि उनके प्रभाव में आकर अधिकारी लोग दबाव में पड़ जायं और अनुचित कार्यवाही कर बैठें । जैसा कि सुना जाता है, फ्रान्स में एक व्यवस्था है कि वहां पर एक आयोग नियुक्त है और वहां जिन अधिकारियों को इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ा है उनको उस आयोग के समक्ष लाकर कहने सुनने का मौका देते हैं । तो इस दृष्टि से ऐसा कदम उठाने के लये सरकार को कुछ न कुछ करना चाहिये जिससे कि चीफ मिनिस्टर्स अपने पद का इस तरह से दुरुपयोग न करें कि उसका अधिकारियों पर नाजायज़ प्रभाव पड़े ।

प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी को भी कम से कम इतना तो बंधन अपने ऊपर रखना चाहिये कि जब तक आरोप प्रमाणित नहीं हो जाते या अप्रमाणित नहीं हो जाते तब तक, उनके बारे में, चाहे वे सही हों या गलत हों कोई स्टेटमेन्ट नहीं देना चाहिये । ऐसा कहा गया कि कांग्रेस दल के अन्दर दो पार्टियां हो गई एक ग्रुप के लोग दूसरे पर आरोप लगाते हैं जिससे प्रधान मंत्री एवं गृह मंत्री को बचना चाहिये । तो होना यह चाहिये कि जैसा संथानम कमेटी ने रिपोर्ट दी कि दस एम०एल०ए० या दस एम०पीज० सिगनेचर्स करके कोई रिपोर्ट दें तो अटार्नीजनरल के पास भेज दीजिए कि अगर प्राइमा फेसी केस भी मिल जाय, तो उसके बारे में कार्यवाही करें, तो अच्छा हागा । इसके लिये हमें जल्दी से निर्णय करना पड़ेगा । हमारे यहां एक पंजाब का ही मसला नहीं है । उड़ीसा के पटनायक साहब के बारे में यहां भी चर्चा चली, बिहार के बारे में भी चर्चा चलती है और अखबारों में भी उसके बारे में खूब निकलता है । मैसूर के निजलिंगप्पा साहब भी उससे अछूते नहीं हैं । माह अगस्त में चीफ़ मिनिस्टर आफ मैसूर के बारे में होम मिनिस्टर साहब को एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, उसमें कई मेम्बरों ने सिगनेचर किये और राष्ट्रपति महोदय को एक मेमोरेन्डम १७-१२-६४ को दिया गया और एक डेपुटेशन मिला जिसमें तीस एम० एल०एज० और २ एम०पीज० हैं । अगर इस पर भी विश्वास नहीं किया गया, तो क्या आप सोचते है कि ऐसे बचाव करने से वहां की लुटिया डूबने से बच जायेगी ? ऐसा करने से उनकी ही लुटिया नहीं डूबेगी आपकी भी डूब जायेगी । (*Time bells rings.*) इस दृष्टि से यह अत्यंत आवश्यक है कि हमारी सरकार इस बारे में शीघ्र निर्णय ले ।

अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप यह जो कानूनी आधार ले कर काम करते हैं उसको पक्षपात के आधार पर मत करिये । हमारा वित्त विभाग जो इतना धन इकट्ठा करता है, सिनेमा एक्टर्स के घरों में जाकर, स्टोर्स में जाकर छापा मारकर पैसा वसूल करता है, अगर यह दास कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि करोड़ों रुपये उन लोगों ने इकट्ठे किये, तो फिर वित्त विभाग के अधिकारी क्यों नहीं जाकर देखते हैं ? क्या

दल के दलदल में फंसे रहने के कारण आप यह समझते हैं कि उनके खिलाफ कार्यवाही की गई, तो कांग्रेस की बदनामी होगी । जब तक आप ऐसा पुण्य का काम नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं करेंगे, छापा नहीं मारेंगे, डाक्युमेन्ट जब्त नहीं करेंगे, जब तक यह सख्त कार्यवाही नहीं करेंगे, तब तक इसको बजाय कांग्रेस की प्रतिष्ठा का प्रश्न कहने के आप उसकी प्रतिष्ठा को भंग करेंगे और आप जैसे लोग उसको नष्ट करने का कारण बनेंगे और अगर आप ईमानदारी से न्याय के आधार पर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे तो कांग्रेस की प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और आप भी बदस्तूर कायम रहेंगे नहीं तो ये तो डूबेंगे ही, साथ में आपको भी ले डूबेंगे ।

The question was proposed.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Each Member who participates in this discussion will have ten minutes.

DR. GOPAL SINGH (Nominated): Madam Deputy Chairman, in considering the Report of the Das Commission, Chordia has been carried away by emotion, not led by reason. He has let the cat out of the bag when at the end of his speech he said that not only Sardar Partap Singh Kairon, but the entire Congress organisation and all the Congress Governments perhaps were corrupt.

SHRI A. B. VAJPAYEE (Uttar Pradesh): No, it is not so.

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चोरड़िया: आप मुझे गलत कोट कर रहे हैं, मैंने प्रोडेक्शन की बात कभी नहीं कही ।

DR. GOPAL SINGH: He particularly named a few Chief Ministers other than the ex-Chief Minister of Punjab . . .

AN HON. MEMBER: Who were under a cloud.

DR. GOPAL SINGH: Many of you are also under a could. I am coming to that.

SHRI AWADESHWAR PRASAD SINHA (Bihar): Madam, we listened to Mr. Chordia silently. Let the other gentlemen also show certain decorum and decency to the House and listen silently.

DR. GOPAL SINGH: I do not think . . .

SHRI LOKANATH MISRA (Orissa): The Rules of the House also admit that there can be interruptions.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Not when each Member is given only ten minutes.

SHRI AWADESHWAR PRASAD SINHA: Then, others can also interrupt.

(*Interruptions.*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Order, order. Dr. Gopal Singh, please continue.

DR. GOPAL SINGH: Mr. Chordia let the cat out of the bag when he said that he wanted to destroy the Congress and not merely Sardar Partap Singh Kairon, but to his chagrin I may inform him that only just now we have learnt that both the bye-elections in the Punjab have been won by the Congress.

SHRI A. B. VAJPAYEE: After the removal of Mr. Kairon, yes.

AN HON. MEMBER: Mr. Kairon supported the Congress in these elections.

(*Interruptions.*)

SHRI AWADESHWAR PRASAD SINHA: He is one of us and we will certainly support him.

(*Interruptions.*)

DR. GOPAL SINGH: Now, are here discussing only the Das Commission

[Dr. Gopal Singh.]

Report and nothing frivolous or extraneous should be brought into the debate. Mr. Chordia has talked of all sorts of things about Punjab going down in production and Mr. Pratap Singh Kairon flourishing at the expense of the State.

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चोरड़या: यह आपकी समझ का फेर है। अगर आप हिन्दी नही समझ सकते तो मै अंग्रेजी में बोल देता।

DR. GOPAL SINGH: You have said that since Mr. Kairon became the Development Minister, it was only his family that developed and not Punjab and I am going to repudiate it.

AN HON. MEMBER: Is that not true?

DR. GOPAL SINGH: It is a lie. It is a malicious lie because if you only go into the report of the Planning Commission or even any non-official reports during the last ten years, you will find that Punjab has progressed more than any other State in the sub-continent of India.

AN HON. MEMBER: Including corruption.

DR. GOPAL SINGH: Today our *per capita* income is the highest. Punjab, which was a deficit province before *partition today is a surplus State . . .*

(*Interruptions.*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: I think, Dr. Gopal Singh, you must get used to address the Chair.

DR. GOPAL SINGH: The progress in industry has also been spectacular. While discussing this Report, the Member opposite said that Mr. Pratap Singh Kairon had been painted in this Report in the blackest of colours, but unfortunately the Das Commission Report itself says that the memorialists levelled against Mr. Pratap Singh Kairon 29 charges, out of which 26 were frivolous and some of the remarks that the hon. Judge had been pleased to make against the memorialists are that they have concocted complete myths, indulged in forgery and fabrication, and baseless, reckless, fantastic, false, preposterous, grotesque and clumsy fabrications were invented with an ulterior motive. Again, the anxiety of the memorialists to discredit their political opponents seemed to have gained ascendency over their regard for the prestige and dignity of their State.

SOME HON. MEMBERS: Shame, shame.

SHRI LOKANATH MISRA: What about the three items that have been established?

DR. GOPAL SINGH: I am coming to that. (*Interruption*) This is indicative of a loss of sense of proportion. All these remarks have been made by Mr. Justice Das, but no notice seems to have been taken by the memorialists or their apologists here in this Parliament or outside and they have only pinned down on Sardar Pratap Singh Kairon almost all the conceivable charges that they could lay their hold on under the sun.

Sardar Pratap Singh Kairon has been held guilty by the Das Commission on three particular, specific counts. These are (1) that he kept for 45 days a doctor irregularly while he was on tour and the doctor had not taken leave as he ought to have. Now, this is an irregularity which is not sufficient to hang the Chief Minister, nor to paint him as a corrupt official, because of the fact that the Chief Minister of a State is a high dignitary, his health is as much the concern of the State as the health of the Prime Minister of this country or the President of this country. Therefore, even if irregularly he had kept with himself for 45 days a doctor—I say irregularly—even then you cannot paint him as a corrupt officer, merely on this count. And this is the only charge that has been levelled against Sardar Pratap Singh Kairon personally. That

is what the Das Commission Report says.

SHRI P. N. SAPRU (Uttar Pradesh): The Prime Minister had very rightly said . . . .

DR. GOPAL SINGH: Now, in the summary of findings, Mr. Justice Das has divided all these charges into three categories. The first category is of the case where the Chief Minister himself abused his influence and power for his own benefit and under this only a single case is quoted against him, that is the case of Dr. H. S. Dhillon, whom he kept for 45 days on tour irregularly. But on this count only, you cannot say that Sardar Pratap Singh Kairon was the most corrupt person, a person who built Punjab, a person who crushed communalism in Punjab, a person who brought prosperity to Punjab, a person who was an asset not only to his State but also to the whole of the country when the defence of India was in jeopardy. It was only Punjab under Sardar Pratap Singh Kairon that stood up to the Chinese aggression as no other State in this country did. Therefore, when you paint him in the blackest of colours, please keep a sense of proportion. Please give even the devil his due. Do not be led away by your emotions or by your Party interests. The interests of the country are dearer to me as they should be dearer to you. Even if Sardar Pratap Singh Kairon has committed any irregularity, has gone, he has been dismissed. Therefore, keep a sense of balance. Do not be misled by slogans. Do not build up your Party's prestige on this, because anybody who builds on wrong foundations will be demolished, as much as Sardar Pratap Singh Kairon was.

Then, I come to the other two charges that have been levelled against him, not against him but against some of the Ministers of his Government, who, it is alleged, in order to please him tried to help his sons. These two cases are the case of the Neelam Cinema in Chandigarh and the case of Nandan Cinema and the Punjab Cold Storage in Amritsar. The third case is about the sale of land in the village of Ramgarh Dhani, etc. Now, I will analyse in two minutes briefly all these three cases.

The case of the Neelam Cinema, Chandigarh, was that while his son had not come forward to bid or tender initially, he was allowed after six months to participate in the lease of the cinema plot with another person, that he was allowed the concession to pay the instalments due from him at a later date than these were originally due. Now, Mr. Talib, the Deputy Minister in charge, has been condemned, I should say unnecessarily in this Report. He has given in his affidavit to the Commission that he had allowed in about a hundred other similar cases the concession to pay their instalments later than they were originally due. I am a refugee myself and I know that lakhs and lakhs of refugees were allowed such concessions. When the instalments fell due and the refugees could not pay in time they had been given further time. I concede that it is irregular, as the Das Commission Report itself points out, but even if it is irregular, is it such a thing as to condemn the man as a murderer, a killer and a criminal? And Mr. Talib has been condemned for the reason that he also signed all those papers allowing these concessions to his sons. Now, I do not see any reason why the hon. Judge should have adjudged on persons who were not concerned with this enquiry directly, because on the initial pages of this Report the learned Judge himself says that he was going to enquire only into the specific charges against Sardar Pratap Singh Kairon and against nobody else. But then he framed other charges against other people also and condemned, unheard, Mr. Talib, Mr. Mohan Lal and Mr. Brish Bhan and some other people also.

Now, the third case was about Nandan Cinema and the Punjab Cold Storage in Amritsar. There is a land,

[Dr. Gopal Singh.]

privately owned, which the son of Sardar Pratap Singh Kairon acquired for Rs. 80,000. He pays the money and the Judge says that the money was paid legally, that he had legal money on him and that the payment was regular. Now, he buys it, but the Judge says that he ought not to have bought it because this land was meant for something else, because the town plan did not envisage the putting up of a cold storage there or a cinema there and there should have been some kind of a housing colony built on this property according to the plan This land was lying vacant for ten years. Nobody had built anything on it. Suddenly this gentleman, the son of Sardar Pratap Singh Kairon, the unfortunate son, comes forward and pays Rs. 80,000 out of his own hard-earned money or from his mother-in-law who is a rich person. He pays Rs. 80,000 and buys this private property from a private person and then goes to the Municipal Committee. The Municipal Committee unanimously decides—including members of the Jan Sangh, including members of the opposition—that the licence should be granted to him. The D.C. also signs the papers. It then goes to the Legal Remembrancer. The Legal Remembrancer says that there is no objection to it, and the Industries Minister, Mr. Mohanlal, also signs the paper. I do not see any reason why Sardar Pratap Singh Kairon or Mr. Mohanlal should be hanged for this and why should they be painted in the blackest of colours.

Thirdly, there is the sale of some surplus land in village Ramgarh Dhani, etc. This land was acquired for the Harijans. Sardar Pratap Singh Kairon on the file of the case notes down that because this land belongs to the mother-in-law of his son, therefore it should not be acquired. He says so in so many words that it belongs to his relations and therefore this land should not be acquired. Giani Kartar Singh Revenue Minister, writes to the Governor, Shri Gadgil. Mr. Gadgil writes to Sardar Pratap Singh Kairon that he should not stand in the way, that it is quite all right that it should be taken over for Harijans for whom the Revenue Minister needs it. So this land was acquired on the specific approval of the Governor. So I do not see any reason why Giani Kartar Singh should be condemned on this count. These are all the charges that have been levelled against Sardar Pratap Singh Kairon and his colleagues, three or four Ministers.

About the rest, if his sons have done anything wrong, if they have done anything illegal, you can do whatever you can to them, under the law. If they have not paid taxes, realise those taxes. If they have built up property illegally, seize that property. But do not for heaven's sake raid and search his village-home; do not for heaven's sake call him a criminal or a murderer; do not for heaven's sake paint him in the blackest of colours as if he is the person who has destroyed everything, and built nothing.

In finishing I would like to quote from the inscription on the birthday cake which was presented to Mr. Churchill on his 90th birthday recently, and this was the inscription given on it:

"In war, determination; in defeat, defiance; in victory, magnanimity."

Thank you, Madam.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL (Gujarat): Madam, after hearing the last speaker and his last remarks, I would suggest that we go with a cake to Sardar Pratap Singh Kairon for all that he has done. Madam, I have been associated with some of the happenings in the Punjab and the voice of the Opposition against the reign of terror that reigned in the Punjab under Sardar Pratap Singh Kairon. I am surprised that there are people here in this House who still can advocate it so boldly and defend the reign of a person which was nothing but a reign of terror. Mr. Ram Pajara

is still a member of the Punjab Assembly. He was beaten up when he came here to the Prime Minister and made his complaint. But how can I blame smaller people?

DR. GOPAL SINGH: Is it in the Report of the Das Commission?

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: When this House discussed the Report, discussed the doings of Sardar Pratap Singh Kairon, several Members of the Opposition pointed out the acts of omission and commission of Sardar Pratap Singh Kairon, pointed out how corrupt he was.

SHRI JOSEPH MATHEN (Kerala): We are not discussing that. We are discussing the Report.

THE DEPUTY CHAIRMAN: We are discussing the Report now.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: I am entitled to quote the background of the events and I want to point out that when this House . . .

SHRI JOSEPH MATHEN: It is the Report we are discussing.

(Interruption)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Order, order.

SHRI SYED AHMAD (Madhya Pradesh): We cannot go berserk.

شری عبدالغنی : میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ گلہ پھاڑ رہے ہیں ، کیا ہم بھی گلا پھاڑیں - ہم آپ کے لئے ناممکن کر دینگے ہاوس کی کاروائی کرنا اگر یہ ایسا کرینگے -

†[श्री अब्दुल गनी : मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह गला फाड़ रहे हैं, क्या हम भी गला फाड़ें ? हम आपके लिये नामुमकिन कर देंग हाउस की कार्रवाई करना, अगर यह ऐसा करेंगे ।]

†[ ] Hindi transliteration.

It is not fair. It is a matter of shame.

SHRI P. N. SAPRU: Madam, may I in all humility point out that Mr. Abdul Ghani has not been described in very favourable terms by the report. He has not been believed . . .

(Interruption.)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Order, order

SHRI LOKANATH MISRA: What is the occassion?

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Patel, you come to the Report.

SHRI SYED AHMAD: He should speak about the Report and nothing more than the Report.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: I would like to submit that in coming to the Report I am entitled to remind the House of the background of the events. I am particularly wanting to quote the letter that the Prime Minister wrote to the Das Commission because that is very important. Why did the Prime Minister write that letter? That was what I was trying to point out. In this House several charges were made. The only thing I said was, there sits the protector of all the corrupt persons. That evening I think it was that the enquiry was announced, and in the letter that we have seen printed the Prime Minister says:

> "The Government had thus to deal with very difficult situations. Sardar Pratap Singh Kairon emerged from this long trial of strength with credit and with enhanced reputation so far as the administration was concerned. The Committee further said that "Sardar Pratap Singh Kairon's reputation, during his long career of public service, has been of a man of personal integrity and of complete freedom from communal bias. He is a man of the people simple in his life and devoting his great energy to the work for which he was responsible. His great virtues partly became his defects. His

[Shri Dahyabhai V. Patel.]

constant tours, more especially in the rural areas, led to a lesser degree of time and interest being given to the normal work of administration, and his anxiety to deal with problems on the spot and with speed led sometimes to his bypassing normal administrative procedures."

This is one certificate by the Prime Minister. In the same letter, paragraph 13, the Prime Minister pays another tribute:

"An even more important consideration to keep before me is the public effect of such advice. For me, as for others, public interest must be the dominant consideration. The Punjab is a border province especially affected by developments with our neighbouring countries. While this has been so ever since Independence, it is very much more so since the emergency that has arisen because of the Chinese invasion. The conditions in the Punjab are therefore of very special importance and nothing should be done which adversely affects the situation there and weakens India's position in this emergency. Fortunately the Punjab, under Sardar Pratap Singh Kairon's leadership, has played a very important part in this emergency and has provided both men and resources in a very considerable degree", etc.

One full page. He is a popular figure in the Punjab both in the civil and the army circles, and to remove him would greatly disturb the people of the Punjab. This is the letter that the Prime Minister wrote to the Das Commission.

AN. HON. MEMBER: Every word of that letter is true.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: Then the last but one paragraph:

"The inquiry should be limited to the charges made in the memorandum to the President on July 13, 1963. Some of the charges made are vague and some others appear to be repetitions. The exact issues to be inquired into should therefore be cleared up on the basis of these charges before the inquiry begins. Also, it would be necessary for those who make the charges to make themselves fully responsible for them. Indeed, in their memorandum, they themselves state that 'the deputationists wish to submit that they are sponsoring the charges with a public sense of responsibility and gravity and hold themselves responsible for the veracity of the same.'"

Madam, on reading this letter, promptly Mr. Abdul Ghani, Member of this House, and Mr. Devi Lal, Leader of the Opposition United Front, said that they took full responsibility of the charges that they made. Madam, I thought that for any person like the Prime Minister, particularly for a person like Prime Minister Jawaharlal Nehru to have given this certificate to a Commission, that was going to enquire into the charges against a certain person was already loading the dice too much in favour of Sardar Pratap Singh Kairon and putting too much of burden on the Judge who was going to look into those cases.

SHRI AWADHESWAR PRASAD SINHA: That is reflection on the Das Commission. He should withdraw it.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: I do not make any reflection. I am very clear.

SHRI P. N. SAPRU: On a point of order. Is it proper to say such a thing against an ex-Chief Justice, that he was influenced by any consideration other than justice?

SHRI DAHYABHAI V. PATEL. Madam, this happened before the enquiry. And after the enquiry what is being done?

THE DEPUTY CHAIRMAN: You have very little time.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: Will you not consider the time taken up by interruptions that these people are making? If, Madam, that is your pleasure I will sit down.

THE DEPUTY CHAIRMAN: No, no. You still have time.

SHRI SYED AHMAD: If it is his pleasure, he might sit down.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: You are not in charge of the House. I wish to say that it was very wrong of the Prime Minister to give a certificate of this type before the enquiry or while the enquiry was being ordered. And you can imagine how difficult it is for any one to give any judgment under these circumstances. And having got the judgement, what has the Government done?

(Interruption by Shri P. N. Sapru)

SHRI A. B. VAJPAYEE: Is it a point of order or anything else?

SHRI V. M. CHORDIA: It is disorder.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: And what is Mr. Krishnaswamy's report? I believe the main charges have been proved. But why is it so uncomfortable to the friends opposite? Why do they go on interrupting like this? After all, Madam, you are giving me only ten minutes and I am wanting to confine myself within those ten minutes if I am allowed to.

SHRI LOKANATH MISRA: Fear of exposure.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: My friend, Mr. Chordia, made a very able speech to which there was absolutely no reply. I am waiting for the Home Minister or whosoever is going to answer to see what reply he makes.

Madam, apart from what appeared in this Commission's Report, we know of the persecutions. We know what happened to Mr. Kapoor. So many other things have happened during this administration. Is there going to be any end to it? You may stop me from speaking but you cannot suppress the verdict of the people, you cannot suppress facts. You cannot suppress what happened to Mr. Ram Piara. Facts are facts. In the enquiry there is a clear condemnation of the then Punjab administration. You can say that condemnation is wrong. And now to deny an enquiry into serious allegations of similar bed-fellows, partners and colleagues, I do not know what to call it. What is happening in Orissa today? I have received a big bundle about what is happening in Mysore. I should like to know what the Home Minister proposes to do about it. They have taken so much fright after the Das Commission Report that they are going to hush up everything; they are going to eat their own words. They promised enquiry into the Orissa affair. Are they going to order it or not? That I should like to know from the Home Minister.

DR. ANUP SINGH (Punjab): Madam Deputy Chairman, we are expected to confine our remarks to the Das Commission and restrain ourselves from wandering all over the universe. I propose to follow that example. I have personally witnessed the unfolding of the carefully organised and conceived plan to discredit not only Sardar Pratap Singh Kairon who has been discredited according to the Das Commission Report, but to utilise that opportunity to discredit the Congress. I am personally convinced that it has been an organised, vicious, venomous campaign carried to the utmost limit. Sardar Pratap Singh Kairon has been dislodged and dismissed but these memorialists having tasted the blood are out to satisfy their lust.

SHRI A. D. MANI (Madhya Pradesh): No lust.

DR. ANUP SINGH: Madam Deputy Chairman, the picture that has been painted by the memorialists and unfortunately by a section of the press, particularly the vernacular press in

[Dr. Anup Singh.]

Punjab, presents Sardar Pratap Singh Kairon as the devil incarnate. Now that picture, unfortunately for the Opposition, does not tally with what is reflected in the Commission's Report itself. My friend, Dr. Gopal Singh, has quoted extensively to establish the fact that only on one single isolated case he has been held personally responsible. He has also shown what is the magnitude of that so-called political crime. In five other charges, in which his colleagues are supposed to have helped his family and in eighteen charges he has been completely vindicated, not only vindicated but very serious aspersion on the integrity of the memorialists has been cast by the Das Commission. I would just refer to one or two remarks that he has made about one of the distinguished Members here, the crusader in this campaign. He says:

> " . . . Maulvi Abdul Ghani Dar has filed an affidavit in reply (R-35) which adds no fresh information but only reiterates that everything was being done under the influence of S. Pratap Singh Kairon."

> " . . . . Maulvi Abdul Ghani evidently believes in repetition of assertions to establish his point of view. There is no tangible evidence in support of his insinuation in this behalf."

Furthermore, he goes on to remark about some other memorialists. Here is one more sample about the integrity of the crusader of this campaign of vilification:

> " . . . and all these reckless allegations have been verified by him as 'true according to the sources indicated in the verification of corresponding paragraphs of M-6' . . . *i.e.*, the affidavit of Maulvi Abdul Ghani Dar who, himself, has no personal knowledge . . . In short the allegation comes to this that this deponent states, on information based on the records of the Allahabad Bank Ltd., that the pass books issued by them are false. Recklessness could hardly go further."

SHRI SYED AHMAD: He should be prosecuted for perjury.

DR. ANUP SINGH: These are the remarks made by the distinguished jurist. Madam Deputy Chairman, I have no desire whatsoever to make any controversial remarks about the Das Commission Report itself. But I am tempted to make one observation as a layman. There was a specific instruction:

> "The Commission has no jurisdiction or power to enquire into or report on any allegations made against any person other than Sardar Pratap Singh Kairon by any person other than Shri Devi Lal and the signatories in any chargesheet other than the memorandum referred to in the Notification. Rule 4 of the Central Commission of Enquiry Act also says that these provisions are mandatory in character and provide for giving them a right of hearing in the following terms . . ."

Dr Gopal Singh has referred to these three cases in which the ex-Ministers—I would not say they have been dismissed but they—have not been included in the new Cabinet because there is a shadow on their integrity. They were never given any hearing. They never submitted any affidavit. The memorialists never even made any reference to them by implication and yet these people had to suffer. May I also remind the Home Minister that these Ministers—I am not holding any brief for them personally—submitted a memorandum in their defence and it has been with the Ministry for the last five months? It has been acknowledged but no action has been taken.

Now much has been said about the background by Mr. Patel. He was trying to give the background of this

controversy. He quoted the late Prime Minister. I might add for his information that not very long ago, only a few months ago, in the Congress Party meeting the late Prime Minister said: "More than 100 M.L.As. came to me today imploring me not to take away Sardar Kairon from them", and jokingly he said: "I assured them that he is not going to Madhya Pradesh. He will be in Punjab because he is very useful". Then the Prime Minister said the following—I am speaking from memory but I think it was exactly like this—and he said:

पैट्रियाटिज्म के लिहाज से, इनिशियेटिव्ह के लिहाज से, सरदार प्रताप सिंह कैरों के पाये का इन्डिया भर में दूसरा आदमी नहीहै ।

"In terms of patriotism, dynamism and initiative there is not a second person who will come anywhere near Pratap Singh Kairon". This was a compliment . . .

SHRI LOKANATH MISRA: That was as a result of mutual compliments.

DR. ANUP SINGH: . . . from the Prime Minister of India, a distinguished Prime Minister. As for the sins of omission and commission of his sons, I think we must recall the Biblical adage that the sins of the father should not be visited upon the sons. This is taking place in the reverse and their sins of omission and commission—real and imaginary—are being visited upon Mr. Kairon. In due deference to the verdict of the Commission, the Congress Party, the Congress Government has dislodged Mr. Kairon. I think that is more than enough. I might say here for the information of the House that there is a growing number of people in Punjab who feel that the punishment has been far in excess of the established guilt of Mr. Kairon.

SHRI A. B. VAJPAYEE: What punishment are you referring to?

DR. ANUP SINGH: Dismissing him from the Chief Ministership is a punishment. Further I might say that there is further persecution and harassment. I am not referring to any particular person but the taking away of his posters and his pictures—in the emergency there were certain posters where Mr. Kairon was trying to mobilise public opinion—and eliminating them from the public scene. We do not follow the example of some of the dictatorial regimes. This will set a bad precedent. Today it is Mr. Kairon, tomorrow it will be somebody else—X, Y or Z. I would request the Home Ministry to see to it that nobody is permitted to indulge in activities which are not very dignified.

One more word and I am through. It might appear that I am trying to exonerate Mr. Kairon. He has been punished and as I said, according to some people, the punishment has been not only sufficient but is in excess but we must seriously remember and not forget Mr. Kairon's past record. I have had the privilege of knowing him for forty years and I can testify, for whatever it is worth, that I have not come across anybody who is endowed both with burning patriotism . . .

SHRI A. D. MANI: All of us are.

(Interruptions.)

DR. ANUP SINGH: . . . and energy. Whatever he saw abroad, his great desire was to come back to India and try to do something here to the prosperity of the people, the people of Punjab and the people of India. He is a man who has suffered long imprisonments in the freedom fight. He was Secretary of the Congress, President of the Congress, Member of the Working Committee, Member of all the Ministries and Chief Minister for ten or eleven years. That is certainly a very commendable record. I may say that we do not want to minimise the importance of the Das Commission report but I do ask the Members to have a sense of proportion, to assess the man properly—his good points and bad points. I thank you.

PROF. M. B. LAL (Uttar Pradesh): Madam, I am sure the House will agree with me that we are much obliged to Dr. Gopal Singh and Dr. Anup Singh for their speeches because their speeches have provided reality to our discussions. They have proved that in this House even a person who for some reason is disgraced can find defenders and that the defence would receive sufficiently careful attention in the House. Dr. Gopal Singh appealed for magnanimity. Though Sardar Kairon is in wilderness, still he is too big to have any treatment of magnanimity from a small man like myself . . .

SHRI AKBAR ALI KHAN (Andhra Pradesh): You are a leader of a party.

PROF. M. B. LAL: So I do not claim to extend any magnanimity to him. But I do assure Dr. Gopal Singh and this House that I wish to consider this question absolutely as a student of political science forgetting that I belong to any particular party because I feel that this particular question and allied questions deserve to be carefully studied by those of us who are entrusted with the task of running the administration and entrusted with the task of promoting healthy growth of democracy and democratic traditions in this country. Dr. Gopal Singh invited our attention to the contribution of Punjab when India was faced with the Chinese aggression. He invited our attention to the economic development of Punjab. We are grateful to the people of Punjab. They stood in the hour of crisis as was expected of them. We are proud of the heroes of Punjab and we do realise that the people of Punjab are very efficient, very hard-working and can stand many difficulties which cannot easily be stood by people of other parts of the country. But I very much doubt whether for all these the credit is due to Sardar Kairon and not to the patriotism, the capacity and efficiency of the people of Punjab.

AN HON. MEMBER: Both.

PROF. M. B. LAL: I am told that he crushed communalism in Punjab.

SHRI AKBAR ALI KHAN: That is a fact.

PROF. M. B. LAL: Many a friend told me that instead of crushing communalism in Punjab he fomented communalism in Punjab so that he may be considered as indispensable by the Congress Party. Some friends of mine do not seem to agree with me. I would be very glad if events prove that I was incorrect but as matters stand today, I feel unconvinced that I am untrue. That Sardar Kairon is a man of energy, is a man of great capacity, that he learnt something in the U.S.A. and tried to utilise that knowledge for the benefit of the people of Punjab and for the people of India cannot be denied. All the same, all that happened in Punjab does not permit me to regard Sardar Pratap Singh Kairon's patriotism as an example for the rest of the country.

5 P.M.

Madam, Dr. Gopal Singh had invited our attention to certain remarks of Justice S. R. Das against the memorialists. If we are prepared to accept Justice S. R. Das's judgment against Sardar Pratap Singh Kairon, his sons and relatives, we have no option but to accept his remarks against certain allegations made by the memorialists. But I do feel, Madam, that for that also we cannot absolve Congress leadership of responsibility to the nation. These allegations were being circulated by the memorialists for more than half a dozen years. If proper notice thereof had been taken and if enquiries had been instituted much before, there would have been a judgment against these unfounded charges by a judicial authority. I beg to submit, Madam, that the charges against Sardar Pratap Singh Kairon, his sons and relatives were very old. In 1958 a representative of the Congress high command

made certain remarks which must have opened the eyes of the high-ups in the Congress Party and the high-ups amongst those responsible for the good administration of the country If due notice thereof had then been taken, I am perfectly sure the country would have been saved from a lot of propaganda, the people of Punjab would have been saved from the agony of living under the shadow of an alleged or real terrorism

THE DEPUTY CHAIRMAN Your time is over You have spoken for ten minutes

PROF. M B LAL I thought you allowed me fifteen minutes Anyway please give two or three minutes more

I think we will not be serving the country if we are not prepared to deal with cases of alleged corruption at the proper moment I am glad that soon after the Das Commission Report was published, Mr Kairon and his friends in the Cabinet were required to leave the Punjab Council of Ministers, and a new Cabinet was set up, and I was told by members of the opposition that this action raised the reputation of Shri Lal Bahadur Shastri and Shri Gulzarilal Nanda, and the people of Punjab began to feel that there were amongst the Congress leaders persons who were prepared to see that real or alleged corruption did not creep into politics and that they stood for a healthy democracy Perhaps it was due to this reputation that the Congress was able to win both the by-elections recently held

SHRI JOSEPH MATHEN People's verdict

PROF M B LAL But I do feel, Madam, that that reputation is being corroded by the delay in action The follow-up is not as it should be Many important affairs are being kept pending and if I mistake not, if I am not wrongly informed, the Chief Minister has begun to be called the pending Minister I further beg to submit Madam, that if Sardar Pratap Singh Kairon had been asked to quit the Punjab Ministry much earlier, the Kamaraj Plan would have had greater impact on the people of India than it did have

DR. ANUP SINGH He offered to resign

PROF. M B LAL Well, he offered to resign, but his resignation was not accepted, and that was our misfortune I again beg to submit, Madam, that there are many charges of corruption against a number of Ministries I hope the Government and the leadership of the country would not allow themselves to suffer from the hesitation, vacillation and complacency from which they suffered in the past, and they will take due steps, so that either the charges are proved false or the person concerned quits office You may cry, I may cry, but these cries do not convince the people For convincing the people proper action at the proper time is needed In August certain charges were levelled against the Mysore Ministry The memorandum was placed before the Union Home Minister, but no action is taken against him Shri Kumbharam Arya, while he was suffering from charges of corruption was appointed the Minister for Home Affairs, and the Orissa case is pending for such a long time

SHRI LOKANATH MISRA The name of 'Kairon' looks respectable compared to Orissa

PROF. M B LAL All the same I beg to submit, Madam

SHRI ARJUN ARORA (Uttar Pradesh) But you will remember that Mr Kumbharam Arya gave the combined opposition a crushing defeat in the by-election

PROF M B LAL I agree with Dr Gopal Singh that it was very regrettable that the village house of Sardar Pratap Singh Kairon was raided in an unauthorised manner by some minor officials of the police

[Prof. M. B. Lal.]

In the end, Madam, I appeal in the name of democracy that all of us, forgetting to which party we belong, should work for the promotion of a healthy democracy and give no shelter to any corrupt Minister or to any corrupt person to whichever party he belongs.

شری عبدالغنی : مسٹر ڈپٹی چیرمین- میں مسٹر نندا اور راشٹرپتی جی کا شکرگزار ہوں کہ انہوں نے یہ کمیشن بٹھایا اور اس کمیشن کا فیصلہ ہاؤس کے سامنے آیا - مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ آفیشل پارٹی آج پتہ نہیں کیوں آپ سے باہر ہو رہی ہے -

حقیقت انلی ہے کہ ۱۹۵۷ع کے آخر میں پنت جی وہاں گئے اور کچھ کانگریس کے ایم - ایل-ایز- نے ان سے شکایت کی - انہوں نے کانگریس پریذیڈنٹ شری یو - این- ڈھیر کو وہاں بھیجا - انہوں نے کہا لکھکر دو - ان کو ایک چارج شیٹ لکھکر دیا گیا جس پر کانگریس ہائی کمانڈ نے - کسی اپوزیشن کے لیڈر نے نہیں - یہ ذمہ دار قرار دیا کہ جو سردار پرتاپ سنگھ کیروں کی دھرم پتنی جنتی گرہ میں بیٹھکر پبلک فنڈ سے پیسہ لیتی رہیں وہ ان کو سمجھتا نہیں تھا - انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے جو کوآپریٹیو کوالٹ اسٹوریج کی بنائی ہے - یہ میں نے نہیں کہا کانگریس ہائی کمانڈ نے کہا - وہ ایک فیملی افیئر ہے اور کوآپریٹیو نہیں ہے - اور پھر یہ کہا کہ پرتاپ سنگھ کیروں ایڈمنسٹریشن میں بھی ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان کو سجتی نہیں - اس لئے ہم اگر ان کو زیادہ نہیں کہتے کہ ان کی ڈائریکٹ کوئی ریسپانسیبلیٹی ہے لیکن وہ کنسٹرکٹیولی ریسپانسیبل ہیں - اس پر انہوں نے اپنا استعفیٰ بھیجا - پنڈت جی کو یہ قبول نہیں ہوا اور انہوں نے استعفیٰ قبول نہیں کیا - اس نے فیل کیا اور اس کو شرم آئی کہ میرے خلاف ہائی کمانڈ نے فتویٰ دیا ہے کیوں کہ ایک دانا آدمی کے لئے اشارہ کافی ہوتا ہے لیکن پنڈت جی نے ریزگنیشن نہیں دینے دیا -

DR. ANUP SINGH: All the files were made available.

شری عبدالغنی : جی ہاں - اب یہی وہ تو آوٹ آف کنٹیڈینس ہے جو کہ آپ کر رہے ہیں اور اس میں کوئی کلام ہے کہا - داس کمیشن کے فیصلہ پر سردار گوپال سنگھ جتنا چاہیں کمینٹ کریں اور تم اس کو انجوئے کرو - اس میں کوئی حرج کی بات تھوڑا ہی ہے -

تو میں یہ کہہ رہا تھا مہدم - کہ اس کے بعد انہوں نے پھر زیادہ اپنی پاور کو ابھوز کرنا شروع کیا اور اس میں ان کی جائیداد جو پہلے ایک پیسہ تھی وہ ایک پیسہ سے ایک روپیہ ہو گئی - پھر کچھ کانگریس ایم-ایل-ایز- نے چارج شیٹ دیا - دونوں

هر دل عزیز ہے جیسا کہ دیا بھائی پٹیل نے پڑھا -

श्री अकबर अली खान : आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर ? पजाब का यह दस्तूर रहा कि जब दो पहलवान लड़ते है और जब कोई गिर जाता है तो उसको सम्भालते है न कि गिरे हुए को और मारा जाता है ।

شری عبدالغنی : میں بھائی اکبر علی خاں سے پھر کبھی نپٹ لوں گا - میرا وقت چھوٹا ہے اور مجھے آپ کہنے دیجئے اس کے بعد جو آپ کے من میں آئے یا آپ کی گورنمنٹ کے من میں آئے اس پر وہ عمل کرے -

میڈم - اس ۱۹۶۰ع کی چارج شیٹ کے بعد جب یہ جائیداد بڑھی تو ہم نے کیا کہا -؟ ہمارا چارج کیا تھا - ہمارا الزام یہ تھا کہ سردار پرتاپ سنگھ کیروں نے ابیوز آف پاور کی ہے - اور اس کی ابیوز آف پاور سے اس کی فیملی نے جائیداد بڑھائی ہے - میں ڈاکٹر انوپ سنگھ اور ڈاکٹر گوپال سنگھ پر چوٹ نہیں کروں گا - وہ خوشی سے جو چاہے کریں - میں انہیں معاف کر دیتا ہوں - تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ہم نے جو چارج لگایا وہ یہ تھا کہ سردار پرتاپ سنگھ کیروں نے ابیوز آف پاور کیا ہے اور اس ابیوز آف پاور سے انہوں نے کروڑوں روپیئے کی جائیداد بنالی ہے - میڈم وہ دوست خفا نہ ہوں جن کو بہت غصہ آتا ہے کیوں کہ پرتاپ سنگھ کیروں کو بھی مانتا پڑا وقت میں بھی تھا - میں نے پہلی بار بھی چارج شیٹ دیا تھا اور دوسری بار بھی میں نے ہی تیار کیا تھا اور ہمارے لیڈر شری پربودھ چندر نے اسے پیش کیا تھا - اس کی جائیداد بڑھ گئی تو پھر ہم نے دوبارہ ۱۹۶۰ع میں کہا کہ آپ نے تو اشارہ کیا تھا لیکن اب تو وہ بالکل کھل کر کھیلنے لگا - پنڈت جی نے اس کو گولڈ اسٹوریج میں ڈال دیا - مسٹر داس یہ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد اور جائیداد بڑھ گئی اور اس میں انہوں نے حصار سنیما اور نیلم سنیما فریدآباد کی لاکھوں کروڑوں روپیئے کی جائیداد بنالی - مسٹر داس کہتے ہیں کہ اس کے بعد جائیداد اور بڑھی اور پھر میمورینلسٹ جن میں کانگریس کے نہیں بلکہ اپوزیشن پارٹیوں کے سب سے ذمہ دار بھائی تھے انہوں نے چارج شیٹ دیا - آپ سے میں عرض کروں کہ جب یہ چارج شیٹ انہوں نے دیا تو اس کا سردار پرتاپ سنگھ کیروں نے جواب بھیجا کانگریس ہائی کمانڈ کو اور ہمارے بزرگ پرائم منسٹر کو جب یہ کمیشن بیٹھ گیا تو پنڈت جی نے پہلے بھی دھمکی دی تھی کہ ان کو خوب زور سے مضبوط ہاتھوں سے تابو کیا جائے جو الزام لگاتے ہیں - کیوں کہ وہ بالکل آنسٹ ہے اور اس نے کوئی برائی نہیں کی - اور وہ بڑا

[شری عبدالغنی]

اس کے بیٹوں کو بھی ماننا پڑا اور نہ مانتے ہوئے بھی ان سب کو ماننا پڑے گا جو یہاں ہیں شیم شیم کہتے ہیں - شرم، شرم انہیں خود آنی چاہئے -

श्री लोकनाथ मिश्र : कांग्रेस वाले शर्म की परवाह नहीं करते ।

شری عبدالغنی : جو ایک کرپٹ چیف منسٹر کو آٹھ برس تک پناہ دیتے رہے - آٹھ برس تک پنڈت جواہر لال نہرو اور یہ بھائی جو آفیشل پارٹی میں بیٹھے ہیں یہ اس کرپٹ چیف منسٹر کو پناہ دیتے رہے - اس لئے یہ خود کرپٹ بن گئے کیوں کہ انہوں نے ملک کو دھوکا دیا - داس کمیشن کا یہ فتویٰ آج موجود ہے - کہ سردار پرتاپ سنگھ کی کنائونس سے یہ ساری جائیداد بنی اور اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے - باوجود اس کے کہ سینٹرل گورنمنٹ نے ڈالمیا کے کیس میں بڑی ڈٹ کر مدد دی اس بات کو ثابت کرنے کے لئے کہ یہ کرپٹ ہے اور اس کو قید بھی کیا لیکن یہاں اس کو بلی سونگھ گئی - اور پنڈت جی نے اس کو چلنے دیا کیوں کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ "دھنی از آنسٹ" "عبدالغنی از ڈس آنسٹ" داس کمیشن ایک انکوائری کمیشن تھا اور اس کو یہ حق نہیں دیا تھا سینٹرل سرکار نے کہ وہ ایک ایک الزام پر تمام گواہیاں لے اور گواہیاں لینے کے بعد فیصلہ کرے - اس کو جو کچھ میسر آیا اس پر قناعت کی - شاید یہ کہتے ہوئے کسی بھائی کو رحم نہیں آیا کہ گورنمنٹ آئے دن اپنے آفیسرس کو پچاس پچاس چارج لگا کر دیتی ہے اور اس میں ایک بھی ثابت نہیں ہوتا اس کے باوجود گورنمنٹ کو ایماندار سمجھتے ہوئے اس نے ایمانداری سے اس کو یہ الزام دیا کہ ان پر کوئی مقدمہ نہیں باندھا - آپ ہمیں وہ درجہ نہ دیں جو اپنی سرکار کو دیتے ہیں کیونکہ ان کے چارجز تمام غلط ثابت ہو جاتے ہیں - اور آفیسرس آٹھ آٹھ سال کے لئے معطل کئے جاتے ہیں - آج بھی منسٹر کپور معطل کئے ہوئے ہیں باوجود اس کے کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلے موجود ہیں - باوجود اس کے کہ وہاں کے جو ہائسٹ آفیسر بیٹھے تھے انہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ ان کو ریسٹیٹ کرنا چاہئے پھر بھی ان کو ریسٹیٹ نہیں کیا گیا - اب پبلک فنڈ سے لاکھوں روپیہ ان کو دیا جائے گا جب کہ ان کو ریسٹیٹ کریں گے - اور پہلے بھی لاکھوں روپیہ دیا - تب میں یہ سمجھتا ہوں کہ باوجود ان سب باتوں کے پریویلیج کلیم کیا گیا - داس صاحب چوں کہ اس موڈ میں نہیں تھے کہ وہ زیادہ وقت لگائیں اور وہ سمجھتے تھے کہ چارج کیا ہے - چارج ہے ابیوز آف پاور - باقی تو مثالیں تھیں جن پر یہ کہتے ہیں کہ یہ

پاور کیا ہے - تم ہمیں برا بھلا کہتے ہو - ہم نے کب یہ کہا کہ اس نے دس روپیئے لے لئے - ہم نے یہ کب کہا کہ اس نے زبردستی کسی کی جیب کاٹ لی - تو جو ہم نے کہا تھا وہ ہوا -

(*Interruption*)

ہاں ہوگا اور وہ ہوکر رہے گا - جب کبھی میں یہاں یہ سوال اٹھاتا تھا تو آپ کہتے تھے کہ مجھے فوبیا ہوا ہے - لیکن وہ فوبیا کہاں گیا - اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ داس کمیشن نے یہ مان لیا کہ اس نے ابیوز آف پاور کیا ہے اور اس کی کنائویلس سے یہ ساری دولت جمع ہوئی ہے - آج وہ چودہ کروڑ روپیئے اپنے پاس رکھتا ہے اور جو انکم ٹیکس پر آپ اس وقت چپکی سادھے ہوئے تھے اور سیل ٹیکس پر جو چپکی سادھے ہوئے تھے آج وہ لاکھوں روپیہ اگل رہا ہے - اس نے بے ایمانی سے دولت اکٹھی کی ہے - اس کے غرور میں آج وہ نڈدا صاحب اور شاستری صاحب کو چیلنج کرتا ہے - اور ایک ایک منٹ پر اسٹیٹمنٹ کرتا ہے - اور وہ اس لئے کرتا ہے کہ ہماری سرکار نے جو ڈالمیاں کے معاملہ میں جو مترا کے معاملہ میں رویہ اختیار کیا وہ پرتاپ سنگھ کیروں کے معاملہ میں رویہ اختیار نہیں کیا-

سردار پرتاپ سنگھ کہتے ہیں . .

پروف نہیں دے سکے - پروف دینا کوئی آسان بات نہیں ہے - جب کہ فائلیں سرکار کے قبضہ میں ہوں اور سرکار کو پریولیج کلیم کرنے کا حق ہو- یہ پریولیج کلیم کرنے کے باوجود داس صاحب یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ اس نے اپنے آفیسرس کو کریٹ کیا اس نے اپنے ایم-ایلیز- کو کریٹ کیا - ساری پارٹی کو قیمورلائز کیا اور آنکھیں بند کرکے اس نے اپنے بیٹوں کو اجازت دے دی -

لوٹ پڑی سو لوٹ - جو نہ لوٹے سو لوٹ

یہ حالات ہوتے ہوئے آپ کیوں خفا ہوتے ہیں - سپرو صاحب کو میں اپنا باپ مانتا ہوں اس لئے جب وہ گالی دیتے ہیں تو مجھے ماں باپ کی گالیاں کبھی کھانے کی نالیاں معلوم ہوتی ہیں اور مجھے کوئی صدمہ نہیں ہوتا ہے - میں سمجھتا ہوں کہ وہ بزرگ ہیں لیکن باقی جو بولتے ہیں ان سے پوچھنا چاہئے کہ اتنے بڑے دیش کے تم اگوا ہو - مہاتما گاندھی کے تم فالور ہو - اس لئے بجائے اس کے کہ تم ایریشیٹ کرو ہماری باتوں کو کہ آٹھ برس تک چیف منسٹر کی تمام سہولتیں سہنے کے باوجود پرائم منسٹر کی تمام سختیاں سہنے کے باوجود اپنے لیگل ریسورسز نہ ہونے کے باوجود اور اپنے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہ ہونے کے باوجود ہم یہ ثابت کر پائے کہ اس نے ابیوز آف

श्री राम सहाय (मध्य प्रदेश) : ग्रान ए प्वाइंट ग्राफ ग्रार्डर । मैं प्वाइट ग्राफ ग्रार्डर के तहत ग्रापकी यह तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि जो साहब ग्रभी बोल रहे हैं उनको क्या यह ग्रधिकार है कि जो बातें दास कमिशन की रिपोर्ट मे नही कही गई हैं उनके ग्रलावा कहे ? उनसे ज्यादा इलजाम वह लगा रहे है ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Ghani, your time is up.

شری عبدالغنی : میں چاھتا ھوں کہ مجھے پانچ منٹ اور دیں -

उपसभापति : ग्रौर पांच मिनट नही मिल सकते ।

شری عبدالغنی : اس لئے کہ مسئلہ تو یہی ھے کہ عبدالغنی ایک طرف اور دوسری طرف تمام آفیشیل پارٹی ھے اور پھر دیکھ لیجئے کہ میں خوش رھتا ھوں -

میرا گوپال سنگھ جی سے کہنا صرف اتنا ھی تھا کہ پنجاب نے جو پیداوار میں ترقی کی وہ ۵۴ - ۵۵ - ۱۹۵۶ع میں کی اور ۵۴-۵۵-۱۹۵۶ع میں شری بھیم سین سچر چیف منسٹر تھے پرتاپ سنگھ کیروں نہیں تھے -

دوسری بات جو میں کہنا چاھتا ھوں کہ رام کشن آج جیتے . . . .

उपसभापति : मिस्टर ग़नी, दूसरी बात कहने के लिए ग्रौर मौका मिलेगा ।

شری عبدالغنی : میں داس رپورٹ پر ھی آتا ھوں - میں عرض یہ کر رھا تھا . .

SHRI N. PATRA (Orissa): We have to assess your say in view of the references made against you in the Das Commission's Report itself—isn't it?

شری عبدالغنی : پاترا جی - آپ اس لئے خفا ھوتے ھیں کہ آپ کے بیجو پٹنائک پر بھی حملہ ھے آپ کے بیرین مترا پر بھی حملہ ھے اور آپ کو اس کی پھر ھوتی ھے -

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Ghani, please wind up.

شری عبدالغنی : میں اپنے ھوم منسٹر سے صرف یہ عرض کرنا چاھتا ھوں کہ یہ رپورٹ سامنے آئی اور آپ نے اپنے قابل اعتماد آفیسر مسٹر کرشنا سوامی کو وھاں بھیجا اور انہوں نے جو رپورٹ بھیجی ھے اگر وہ رپورٹ ھمارے خلاف ھے - یہ ھے کہ اس نے ابیوز آف پاور نہیں کیا اور اس کی وجہ سے کروڑوں روپیہ نہیں بنایا تو بے شک اس پر مقدمہ نہ چلائیے اور اگر رپورٹ ھمارے حق میں ھے تو چلائیے - آپ ھمیں موقعہ دیجئے ھم مقدمہ چلائیں گے - اور جیسا کہ یہ صاحبان کہتے ھیں ھم خود وہ مقدمہ برداشت کریں گے - پنڈت جواھر لال نہرو نے دھمکی دی تو میں نے کہا کہ یا تو وہ جیل میں جائے گا یا میں جیل میں جاؤں گا - اس وقت میں نے یہ قبول کیا تھا اور آج بھی یہ قبول کرتا ھوں - آپ جتنا چاھیں میرے خلاف کریں مجھکو پھانسی دیں - لیکن آپ ڈیموکریسی کو قتل نہ کیجئے آپ انسٹی کو قتل

ڈر گئے ہیں کہ کانگریس اس سے کمزور ہو جائے گی -

میں نندا صاحب کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ آنسٹ ہوم منسٹر ہوں آپ دل سے چاہتے ہوں کہ کرپشن دور ہو تو اس سے کبھی کمزوری نہیں ہوتی - سرجن کی طرح جو حصہ گندا ہے اس کو کاٹ دیجئے - کاٹنے سے آفیشیل پارٹی کو کچھ نقصان نہیں ہوگا بلکہ آفیشیل پارٹی کو طاقت ملے گی - جو خون گندا ہے اس کو نکال دیں بجائے اس کے کہ اس کا زہر سارے جسم میں پھیلایا جائے - اس سے کانگریس بچ جائے گی - پرتاپ سنگھ کیروں کے نہ ہوتے ہوئے بھی بھو بھی آپ جیتے ہیں - تو آپ کو خیال کرنا چاہیئے - کیا رامکشن شراب کی وجہ سے یا روپیہ دے کر جیتا ہے - مگر وہ ویسے جیتا ہے - تو اس کے معنی ہیں کہ وہ پرتاپ سنگھ کیروں سے زیادہ ہے - کبھی کرنی پارٹی ایک آدمی کے بھروسہ پر نہیں چلتی ہے -

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Ghani, will you please wind up?

شری عبدالغنی : تو آپ اس کے خلاف مقدمہ چلائیے - مگر آپ مقدمہ نہیں چلاتے - صرف اتنا ہی کہتا ہے اپنے ان ساتھیوں سے جو کہ گلہ پھاڑتے ہیں - ان سے ایک ایک سے کچھ نہیں کہوں گا - ان کو ادھیکار ہے وہ جو جی میں آئے کہیں - آپ نے نہ کیجئے صرف اس لئے کہ وہ آپ کا ساتھی تھا وہ ہمارا ساتھی تھا - ایک ساتھی نکلا بھی نیک کہوں نہ ہو لیکن اگر اس سے بھول ہو جائے وہ چوری کر لے تو اسے معاف نہیں کیا جاتا - اس کو معاف نہ کیجئے اس لئے کہ پہلے بڑا ایمان دار تھا اور اب چوری کی ہے - تو میری نندا صاحب سے درخواست تھی کہ اس کے اوپر مقدمہ چلے اور مقدمہ چلا کر موقہ دیں کہ سپریم کورٹ تک جائے- پھر وہ بچتا ہے یا بچتا نہیں ہے یہ دیکھا جائے - اگر وہ بچ جائے گا تو میں اپنے کو قتل کر دوں گا ہراکری کر لوں گا - کم سے کم جو گالی آپ مجھے دیتے تھے وہ گالی تو نہ ہو -

میں اور کچھ نہیں کہتا - اتنی ہی درخواست ہے کہ وہ کرپٹ تھا داس کمیشن نے اس کو کرپٹ قرار دیا اور اس کے کرپشن کو دبانے سے میسور میں اڑیسہ میں راجستھان میں کشمیر میں کرپشن ہوا - تو جہاں اس کے خلاف مقدمہ چلانا چاہیئے اس کو ایلیمنٹ کرنا چاہیئے وہاں سر کے ساتھ باقی جو اور چیف منسٹرس ہیں ان پر بھی مقدمہ ہو - اگر ہم ثابت نہ کریں کہ انہوں نے ابیوز آف پاور کیا تو ہم اپنے کو جیل بھجوانے کے لئے ہر منٹ تیار ہیں اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہوں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ

[شری عبدالغنی]

ایمان داری سے جیسا کہ اس وقت همت دلائی پنڈت جی کے مخالفت کے باوجود یہ کمیشن بٹھانے کی جرائت کی ویسے هی آپ اس رپورٹ کو امپلیمینٹ کرکے ملک کی مدد کیجئے - میری مدد نہ کیجئے مجھے کوئی دکھ نہیں -

†[**श्री अब्दुल गनी** (पंजाब) मैडम डिप्टी चेयरमैन, मैं मिस्टर नन्दा और राष्ट्रपति जी का शुक्रगुज़ार हू कि उन्होने यह कमीशन बिठाया और इस कमीशन का फैसला हाउस के सामने आया । मुझे इस बात का दु ख है कि आफिशियल पार्टी आज पता नही क्यो आप से बाहर हो रही है ।

हकीकत इतनी है कि १९५७ ई० के आखिर मे पत जी वहा गये और कुछ काग्रेस के एम०एल०एज० ने उन से शिकायत की । उन्होने काग्रेस प्रेजिडेट श्री यू० एन० ढेबर को उसे भेजा । उन्होने कहा लिख कर दो । उनको एक चार्ज शीट लिखकर दिया गया जिस पर काग्रेस हाई कमाड ने——किसी अपोजीशन के लीडर ने नही——यह जिम्मेदार करार दिया कि जो सरदार प्रताप सिह कैरो की धर्मपत्नी चडीगढ मे बैठकर पब्लिक फण्ड से पैसा लेती रही वह उन को सजता नही था । उन्होने यह कहा कि उन्होने जो को-आपरेटिव कोल्ड स्टोरेज बनाई है । यह मैंने नही कहा काग्रेस हाई कमाड ने कहा—— वह एक फेमिली अफैयर है और को-आपरेटिव नही है । और फिर यह कहा कि प्रताप सिह कैरो एडमिनिस्ट्रेशन मे भी ऐसी बाते करते है जो उनकी सजती नही । इसलिये हम अगर उनको ज्यादा नही कहते कि उन की डायरेक्ट कोई रेस्पोसिबिलिटी है, लेकिन वह कस्ट्रक्टिवली रेस्पोसिबिल है । इस पर उन्होने अपना इस्तीफा भेजा । पडित जी को यह कबूल नही हुआ और उन्होने इस्तीफा कबूल नही किया । उस ने फील किया और उसको शर्म आई कि मेरे खिलाफ हाई कमाड ने फतवा दिया है क्योकि एक दाना आदमी के लिये इशारा काफी होता है लेकिन पण्डित जी ने रेजिगनेशन नही देने दिया ।

DR ANUP SINGH All the files were made available

श्री अब्दुल गनी जी हा, अब भी वह तो आउट आफ काफिडेन्स है जो कि आप कर रहे है और इस मे कोई कलाम है क्या ? दास कमीशन के फैसले पर सरदार गोपाल सिंह जितना चाहें कमेंट करे और तुम इसको एन्जाए करो इस में कोई हर्ज की बात थोडी ही है ।

तो मे यह कह रहा था, मैडम, कि इस के बाद उन्होने फिर ज्यादा अपनी पावर को एब्यूज करना शुरू किया और इस में उनकी जायदाद जो पहले एक पैसा थी वह एक पैसा से एक रुपया हो गई । फिर कुछ काग्रेस एम० एल० एज० ने चार्जशीट दिया । दोनो वक्त मैं भी था । मैं ने पहली बार भी चार्जशीट दिया था और दूसरी बार भी मैं ने ही तैयार किया था और हमारे लीडर श्री प्रबोध चन्द्र ने उसे पेश किया था । उसकी जायदाद बढ गई तो फिर हम ने दोबारा १९६० ई० मे कहा कि आपने तो इशारा किया था लेकिन अब तो वह बिल्कुल खुल कर खेलने लगा । पडित जी ने उसको कोल्ड स्टोरेज मे डाल दिया । मिस्टर दास यह कहते है कि फिर इसके बाद और जायदाद बढ़ गई और इस मे उन्होने हिसार सिनेमा और नीलम सिनेमा फरीदाबाद की लाखो-करोडो रुपये की जायदाद बना ली । मिस्टर दास कहते हैं कि इसके बाद जायदाद और बढी और फिर मेमोरियलिस्ट जिन मे काग्रेस के नही बल्कि अपोजीशन पार्टियो के सब से जिम्मेदार भाई

†[ ] Hindi transliteration

थे उन्होने चार्जशीट दिया । आप से मैं अर्ज़ करूं कि जब यह चार्जशीट उन्होने दिया तो उसका सरदार प्रताप सिह कैरों ने जवाब भेजा कांग्रेस हाई कमान्ड को और हमारे बुजुर्ग प्राइम मिनिस्टर को । जब यह कमीशन बैठ गया तो पंडित जी ने पहले भी धमकी दी थी कि उनको खूब जोर से मज़बूत हाथो से काबू किया जाये जो इलजाम लगाते है, क्योकि वह बिल्कुल आनेस्ट है और उसने कोई बुराई नहीं की, और वह बड़ा हरदिलअजीज़ है जैसा कि डाहया भाई पटेल ने पढा ।

श्री अकबर अली खान आन ए प्वाइंट आफ आर्डर । पंजाब का यह दस्तूर रहा कि जब दो पहलवान लड़ते है और जब कोई गिर जाता है तो उसको सभालते हैं न कि गिरे हुए को और मारा जाता है ।

श्री अब्दुल ग़नी : मैं भाई अकबर अली खान से फिर कभी निबट लूगा मेरा वक्त छोटा है और मुझे आप कहने दीजिए । इसके बाद जो आप के मन में आए या आप की गवर्नमेंट के मन में आए उस पर वह अमल करे ।

मैडम, इस 1960 ई० की चार्जशीट के बाद जब यह जायदाद बढ़ी तो हम ने क्या कहा ? हमारा चार्ज क्या था? हमारा इलज़ाम यह था कि सरकार प्रताप सिह कैरो ने एब्यूज़ आफ पावर की है । और उस की एब्यूज़ आफ पावर से उस की फैमिली ने जायदाद बढ़ाई है । मै डाक्टर अनूप सिह और डाक्टर गोपाल सिंह पर चोट नही करूंगा । वे खुशी से जो चाहें करे । मै उन्हे माफ कर देता हू । तो मै यह अर्ज़ कर रहा था कि यह हम ने जो चार्ज लगाया वह यह था कि सरदार प्रताप सिह कैरों ने एब्यूज़ आफ पावर किया है और इस एब्यूज आफ पावर से इन्होंने करोड़ो रुपये की जायदाद बना ली है मैडम, व दोस्त खफान हो जिन को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि प्रताप सिंह कैरों को भी मानना पड़ा, उसके बेटों को भी मानना पड़ा, और न मानते हुए भी उन सब को मानना पडेगा । जो यहा है शेम शेम कहते है । शर्म , शर्म उन्ह खुद आनी चाहिए .....

श्री लोक नाथ मिश्र काग्रेस वाले शर्म की परवहा नही करते ।

श्री अब्दुल ग़नी : जो एक करप्ट चीफ मिनिस्टर को आठ बरस तक पनाह देते रहे । आठ बरस तक पण्डित जवाहरलाल नेहरू और ये भाई जो आफिशियल पार्टी मै बैठे हैं ये इस करप्ट चीफ मिनिस्टर को पनाह देते रहे । इस लिए ये खुद करप्ट बन गये क्योकि इन्होने मुल्क को धोका दिया । दास कमीशन का यह फतवा आज मौजूद है कि सरदार प्रताप सिह की कनाइवेन्स से यह सारी जायदाद बनी और इसको कोई इनकार नही कर सकता । बावजूद इसके कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने डालमिया के केस मे बड़ी डट कर मदद दं इस बात को साबित करने के लिए कि यह करप्ट है; उस को कैद भी किया; लेकिन यहा इसको बिल्ली सूघ गई । और पण्डित जी ने इसको चलने दियाँ क्योकि वह यह समझते थे कि "ही इज आनेस्ट, अब्दुल ग़नी इज़ डिसआनेस्ट" ।

दास कमीशन एक इक्वायरी कमीशन था और उसको यह हक़ नही दिया था सेन्ट्रल सरकार ने कि वह एक एक इलज़ाम पर तमाम गवाहिया ले और गवाहिया लेने के बाद फैसला करे । उसको जो कुछ मयस्सर आया उसी पर क़नायत की । शायद यह कहते हुए किसी भाई को रहम नही आया कि गवर्नमेंट आये दिन अपने आफीसर्स को पचास पचास चार्ज लगाकर देती है और इसमें एक भी साबित नही होता । इसके बावजूद गवनमेंट को ईमानदार समझते हुए उस ने ईमानदारी से इस को यह इलज़ाम दिया कि इन पर कोई मुकदमा नही बांधा । आप हमे वह दर्जा न दें जो अपनी सरकार को देते है क्योकि उनके चार्जिज तमाम गलत साबित हो जाते है और आफिसर्स आठ आठ साल के लिये मुअत्तल किये जाते है । आज भी मिस्टर कपूर मुअत्तल किये हुए है । बावजूद

[श्री अब्दुल गनी]

इसके कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले मौजूद हैं, बावजूद इसके कि वहां के जो हाइएस्ट आफिसर बैठे थे उन्होंने यह फतवी दिया था कि इनको रिस्टेट करना चाहिए, फिर भी इनको रिस्टेट नहीं किया गया । अब पब्लिक फंड से लाखों रुपये इनको दिया जायेगा जबकि इनको रिस्टेट करेंगे । और पहले भी लाखों रुपया दिया । तब मैं यह समझता हूं कि बावजूद इन सब बातों के प्रिविलेज क्लेम किया गया । दास साहब चूंकि इस मूड मे नहीं थे कि वह ज्यादा वक्त लगायें और वह समझते थे कि चार्ज क्या है । चार्ज है एब्यूज आफ पावर । बाकी तो मिसालें थीं जिन पर यह कहते हैं कि यह प्रूफ नहीं देस के । प्रूफ देना कोई आसान बात नही है जबकि फाइलें सरकार के कब्जे में हों और सरकार को प्रिविलेज क्लेम करने का हक हो । यह प्रिविलेज क्लेम करने के बावजूद दास साहब यह कहने पर मजबूर हुए कि इसने अपने आफिसर्स को करप्ट किया इसने अपने एम० एल० एज० को करप्ट किया, सारी पार्टी को डिमारेलाइज किया और आखें बन्द करके इसने अपने बेटों को इजाजत दे दी ।

लूट पड़ी सो लूट, जो न लूटे सो लूट ।

यह हालत होते हुए आप क्यों खफा होते हैं । सप्रू साहब को मैं अपना बाप मानता हूं । इसलिये जब वह गाली देते है तो मुझे मां बाप की गालियां घी खांड की नालियां मालूम होती हैं, और मुझे कोई सदमा नहीं होता है । मैं समझता हूं कि वह बुजुर्ग हैं लेकिन बाकी जो बोलते हैं इनसे पूछना चाहिए कि इतने बड़े देश के तुम अगुआ हो, महात्मा गांधी के तुम फालोअर हो । इसलिये बजाए इसके कि तुम एप्रिशियेट करो हमारी बातों को कि आठ बरस तक चीफ मिनिस्टर की तमाम सख्तियां सहने के बावजूद, प्राइम मिनिस्टर की तमाम सख्तियां सहने के बावजूद अपने लीगल रिसोर्सज न होने के बावजूद और अपने पास कोई डाकूमेंट न होने के बावजूद हम यह साबित कर पाये कि उसने एब्यूज आफ पावर किया है, तुम हमें बुरा भला कहते हो । हमने कब यह कहा कि इसने दस रुपये ले लिये, हमने यह कब कहा कि इसने जबरदस्ती किसी की जेब काट ली । तो जो हमने कहा था वह हुआ ।

(*Interruption*)

हां होगा और वह होकर रहेगा । जब कभी मैं यहा यह सवाल उठाता था तो आप कहते थे कि मुझ फोबिया हुआ है । लेकिन वह फोबिया कहां गया ? इसका नतीजा यह हुआ कि दास कमीशन ने यह मान लिया कि इसने एब्यूज आफ पावर किया है और इसके कनाइवेंस से यह सारी दौलत जमा हुई है । आज वह चौदह करोड़ रुपये अपने पास रखता है और जो इंकम टैक्स पर आप इस वक्त चुपकी साधे हुए थे और सेल टेक्स पर जो चुपकी साधे हुए थे आज वह लाखों रुपया उगल रहा है । इसने बेईमानी से दौलत इकटठी की है । इसके गरूर में आज वह नन्दा साहब और शास्त्री साहब को चेलेंज करता है और एक एक मिनट पर स्टेटमेन्ट करता है और वह इस लिये करता है कि हमारी सरकार ने जो डालमियां के मामले में, जो मित्रा के मामले में रवय्या अख्तियार किया, वह रेवय्या प्रताप सिह कैरों के मामले में अखत्यार नहीं किया । सरदार प्रताप सिंह कहते हैं ...

श्री राम सहाय (मध्य प्रदेश): आन ए प्वाइंट आफ आर्डर मैं प्वाइंट आफ आर्डर के तहत आपकी यह तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि जो साहब अभी बोल रहे हैं उनको क्या यह अधिकार है कि जो बातें दास कमीशन की रिपोर्ट में

नही कही गयी है उनके इलावा कहे ? उनसे ज्यादा इल्जाम वह लगा रहे है।

THE DEPUTY CHAIRMAN. Mr. Ghani, your time is up.

श्री अब्दुल ग़नी : मै चाहता हू कि मुझे पांच मिनट और दे।

उपसभापति : और पाच मिनट नही मिल सकते।

श्री अब्दुल ग़नी . इसलिए कि मसला तो यही है कि अब्दुल गनी एक तरफ, और दूसरी तरफ तमाम आफीसियल पार्टी है और फिर देख लीजिए कि मैं खुश रहता हू।

मेरा गोपाल सिह जी से कहना सिर्फ इतना ही था कि पंजाब ने जो पैदावार मे तरक्की की वह १९५४–५५–५६ ई० में की और १९५४–५५–५६ ई० मे श्री भीम सैन सच्चर चीफ मिनिस्टर थे, प्रताप सिह कैरों नही थे।

दूसरी बात जो मै कहना चाहता हूं कि राम किशन आज जीते....

उपसभापति : मि० गनी दूसरी बात कहने के लिए और मौका मिलेगा।

श्री अब्दुल ग़नी : मै दास रिपोर्ट पर ही आता हू, मैं अर्ज यह कर रहा था...

SHRI N. PATRA (Orissa): We have to assess you say in view of the references made against you in the Das Commission's Report itself—isn't it?

श्री अब्दुल ग़नी : पात्र जी, आप इसलिए खफा होते है कि आपके बीजू पटनायक पर भी हमला है, आपके बीरेन मित्र पर भी हमला है और आपको इसकी पीड़ होती है।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Ghani, please wind up.

श्री अब्दुल गनी : मैं अपने होम मिनिस्टर से सिर्फ यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह रिपोर्ट सामने आई और आपने अपने काबिलेइतमाद आफिसर मि० कृष्णास्वामी को वहा भेजा और उन्होंने जो रिपोर्ट भेजी है, अगर वह रिपोर्ट हमारे खिलाफ है, यह है कि उसने एब्यूज़ आफ पावर नही किया और इसकी वजह से करोड़ों रुपया नही बनाया, तो बेशक उस पर मुकदमा न चलाइए और अगर रिपोर्ट हमारे हक मे है, तो चलाइए। आप हमें मौका दीजिए हम मुकदमा चलाएंगे। और जैसा कि ये साहेबान कहते है हम खुद वह मुकदमा बर्दाश्त करेंगे। पं० जवाहरलाल नेहरू ने धमकी दी तो मैंने कहा कि या तो वह जेल मे जाएगा या मैं जेल मे जाऊंगा। उस वक्त मैंने यह कबूल किया था और आज भी यह कबूल करता हूं। आप जितना चाहे मेरे खिलाफ करे, मुझको फांसी दीजिए लेकिन आप डेमोक्रेसी को कत्ल न कीजिए, आप आनेस्टी को कत्ल न कीजिए। सिर्फ इसलिए कि वह आपका साथी था, वह हमारा साथी था—एक साथी कितना ही नेक क्यो न हो लेकिन अगर उससे भूल हो जाए वह चोरी कर ले तो इसे माफ नही किया जाता—उसको माफ न कीजिए इसलिए कि पहले बडा ईमानदार था और अब चोरी की है। तो मेरी नन्दा साहब से यह दरख्वास्त थी कि उसके ऊपर मुकदमा चले और मुकदमा चलाकर मौका दें कि सुप्रीम कोर्ट तक जाए। फिर वह बचता है या बचता नही है—यह देखा जाय। अगर वह बच जायेगा तो मै अपने को कत्ल कर दगा, हाराकिरी कर लूगा, कम से कम जो आप गाली मुझे देते थे वह गाली तो न हो।

मैं और कुछ नही कहता इतनी ही दरख्वास्त है कि वह करप्ट था। दास कमीशन ने उसको करप्ट करार दिया। और उसके करप्शन को दबाने से मैसूर में, उडीसा में

[श्री अब्दुल गनी]

राजस्थान में, कश्मीर में करप्शन हुआ। तो जहां इसके खिलाफ मुकदमा चलाना चाहिए इसको इम्पलीमेंट करना चाहिए वहां इसके साथ बाकी जो और चीफ मिनिस्टर्स हैं उन पर भी मुकदमा हो। अगर हम साबित न करें कि इन्होंने एब्यूज आफ पावर किया तो हम अपने को जेल भिजवाने के लिए हर मिनट तैयार है, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसके माने यह हैं कि आप डर गये हैं कि कांग्रेस इससे कमजोर हो जाएगी।

मैं नन्दा साहब को यकीन दिलाता हूं कि आप आनेस्ट होम मिनिस्टर हों, आप दिल से चाहते हों कि करप्शन दूर हो तो इससे कभी कमजोरी नही होती। सर्जन की तरह जो हिस्सा गन्दा है उसको काट दीजिए। काटने से आफीशियल पार्टी को कुछ नुकसान नहीं होगा बल्कि आफीशियल पार्टी को ताकत मिलेगी। जो खून गन्दा है उसको निकाल दें, बजाय इसके कि इसका जहर सारे जिस्म में फैलाया जाए।इससे कांग्रेस बच जाएगी। प्रताप सिह कैरों के न होते हुए भी फिर भी आप जीते हैं, तो आपको खयाल करना चाहिए कि क्या रामकिशन शराब की वजह से या रुपए देकर जीता है। मगर वह वैसे जीता है, तो इसके माने हैं कि वह प्रताप सिंह कैरों से ज्यादा है। कभी कोई पार्टी एक आदमी के भरोसे पर नहीं चलती है।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Ghani, will you please wind up?

श्री अब्दुल गनी : तो आप इसके खिलाफ़ मुकदमा चलाइए, मगर आप मुकदमा नहीं चलाते। सिर्फ इतना ही कहना है अपने इन साथियों से जो कि गला फाड़ते हैं। इनसे एक एक से कुछ नहीं कहूंगा। इनको अधिकार है कि वह जो जी में आए कहें। आपने ईमानदारी से जैसा कि इस वक्त हिम्मत दिलायी, पंडित जी की मुखालिफत के बावजूद यह कमीशन बिठाने की जुरायत की वैसे ही आप इस रिपोर्ट को इम्पलीमेन्ट करके मुल्क की मदद कीजिए। मेरी मदद न कीजिए मुझे कोई दुःख नहीं है।]

SHRI P. N. SAPRU: Madam Deputy Chairman, in the comparatively balanced speech which Mr. Mukut Behari Lal made this afternoon, he posed a very relevant question. He asked why action had not been taken earlier against Mr. Kairon, why a Commission of Inquiry had not been appointed earlier than the date on which it was actually appointed. Madam Deputy Chairman, we are working in this country a quasi-Federal Constitution. Chief Ministers of States are responsible to their legislatures; they are responsible to their electorate through their legislatures. They have no responsibility to this House. The Prime Minister has no special power over the Chief Ministers of States. I have not been able to find any provision in the Constitution which empowers the President to appoint a Commission of Inquiry such as was appointed for this purpose. I know that action was taken under section 3 of the Commission of Inquiry Act. Mr. Justice Das, the ex-Chief Justice of India, did not raise this point but it is permissible to doubt whether a Commission could have been at all appointed by the Federal Government. That, I think is the reason which explains the delay and the resitation which the late Prime Minister must have felt in appointing this Commission which might make the working of a Federal Constitution in this country well nigh impossible. I say "wellnigh impossible" because fortunately or unfortunately we have one Party in all the States running the Governments. We cannot imagine the state of affairs in which we shall have a dozen or half a dozen parties, other than the Congress, in the States We do not know what the position then will be.

Madam Deputy Chairman, concluding his Report, Mr. Das has quoted

from the pregnant remarks of one of the great builders of English law, Lord Mansfield. He says:

> "I will not avoid doing what I think is right, though it should draw on me the whole artillery of libels; all that falsehood and malice can invent or the credulity of a deluded people can swallow."

Mr. Das is one of our great legal giants and he has written this Report with that carefulness, with that ability which one associates with his age but I am surprised to find that men who are seeking equity went to Mr. Das's tribunal with unclean hands. It is one of the principles which are embedded in our system of jurisprudence that a man who seeks equity must do equity himself, must go to a court with clean hands. I regret to have to say, on the basis of the various remarks in the body of the Report that ex-Chief Justice Das had a very poor opinion of the veracity of my hon. friend, Mr. Abdul Ghani Dar. He had a very poor opinion of the veracity of the memorialists before him. True, he came to the conclusion that there were three charges of which Mr. Kairon was guilty. Now to some of those charges our family system is responsible. We have got in this country a little too much regard for our nephews and nieces and our sons and grandsons and it often happens that a powerful man finds himself powerless to deal with a strong wife or a strong children. That, I think, has been the tragedy of Mr. Kairon.

When we had this Akali trouble and Master Tara Singh was fasting, I happened to be dining with a very distinguished Punjabi who is not a politician but who is a very honourable man and I asked him what he thought of Mr. Kairon. He said, "Look, do not attack Mr. Kairon: support him. The administration of the Punjab will be impossible without Kairon. He is completely hundred per cent non-communal." That I think is a great tribute to Mr. Kairon considering that that tribute come from a man who himself had been associated at one time of his life with communal politics. There is no doubt that Mr Kairon rendered signal service to Punjab during the time that he was Chief Minister. Educationally it made rapid advances so much so, that today we find our Education Minister highly praising the work that was done in Punjab and telling the country that Punjab is prepared for education being made a concurrent subject. He was fair as between Hindus and Muslims in that border State; he helped the war effort of the country; he put dynamism into the Administration. Possibly he had his own weaknesses but may I just in all humility suggest to the Home Minister who is very strong about corruption that England was corrupt in the days of Walpole but yet it made very great progress? Clive was corrupt and yet he built the British Empire in India. Therefore I think it is important that we who believe in the democratic process should have a balanced outlook on this matter of corruption. We should not rush to the conclusion that everything that is happening in this country is corrupt.

Very severe strictures—I do not want to repeat all those strictures—have been passed by Mr. Justice Das against Mr. Abdul Ghani. Now I think as a man of honour he should endeavour somehow, in some shape or other, to vindicate himself and show them those charges which Mr. justice Das has levelled are not true. May I also say that in law the construction of 'fraud' is a very wide one? The House of Lords felt that reckless statements made without regard to their truth or untruth is fraud. Now that is the authoritative definition given by the highest court in Britain and that is the definition which is accepted by our courts in this country. May I say that some of our friends who are responsible for memorialising the President were guilty of fraud at all events in that sense of the term. They did not have any regard for truth. It did

[Shri P N Sapru]

not matter to them whether the charge was true or whether the charge was false provided the charge was one which would hit Mr. Kairon That was the object, that was the outlook with which they went to Mr Justice Das May I also say that so far as the Kairon chapter is concerned, it is closed now? May I remind the House that against Mr J H Thomas who was one of the builders of the labour movement in England—he was a leader of front rank and he might have become the Prime Minister of Britain—there were some charges, not of a very very serious character but of a fairly serious character? He resigned and the people forgave him for all that he had done They only remembered the good that was associated with his name, they did not remember the evil for which he was responsible

PROF. M B LAL Hope our public men will follow the example of Mr Thomas

SHRI P N SAPRU That I think is the spirit in which, Madam Deputy Chairman, we, whether of the Government Benches or of the Opposition Benches, should work The Opposition cannot make itself strong by just attacking in season and out of season the Government in power They must have a constructive approach to problems What is distressing for lovers of democracy—and I believe in a two-party system of Government—is that our Opposition parties are yet to learn what responsibility is With these words I would like to congratulate the Government on the action that they have taken and I would say that bygones should be bygones

SHRI A D MANI Madam Deputy Chairman, my hon friend, Dr Gopal Singh, asked us not to call Sardar Partap Singh Kairon a criminal or a murderer Nobody on this side of the House has ever said that he is a criminal or a murderer What the Opposition and the memorialists have said in the past and would repeat now is that his conduct was of such a character that he is unfit to be the Chief Minister of Punjab This was the allegation made against Sardar Partap Singh Kairon

Now, my hon friend, Dr Anup Singh said that eighteen charges were proved to be without foundation out of twenty-six Madam, when the Opposition in the country tries to bring such charge-sheets against a formidable person like Sardar Partap Singh Kairon who not only had a legislative majority in the Punjab but who had the confidence of the late Prime Minister at that time it is not possible for them to get all the facts in respect of all the charges If eighteen charges were proved to be false, eight were proved to be correct That itself justifies the memorial that was submitted to the President

My hon friend, Mr Sapru, quoted the case of Mr Thomas and said that after he retired from public life there was a good deal of sympathy for him I do not believe in carrying on a vendetta against Sardar Partap Singh Kairon, if Sardar Partap Singh Kairon retires from public life today we would have no objection whatever to keeping his name out of all controversy but he is trying to stage a comeback and he has got supporters in the Congress Party also who seem to look upon the great achievements of his as offsetting completely his misdeeds It is for that reason I have to say that this Report has to be discussed in this House and we have to express our opinion

Madam, I would like to say that I have not been satisfied with the procedure of this inquiry I feel that whenever Chief Ministers or Ministers are changed with misconduct, the trial should take place under the Public Servants (Inquiries) Act, 1850 There was only one trial under the Public Servants (Inquiries) Act and that was many years ago when Mr S A Venkataraman who was a member of the Civil Service and who was the Secretary of the Industries Department was publicly tried Witnesses were put on the witness stand and they were exa-

mined and cross-examined. I would have been very happy if Sardar Partap Singh Kairon and the memorialists including Mr. Abdul Ghani had taken the witness stand and allowed their motives and their attitudes to be examined and cross-examined by the counsels. It would have done a lot of good to the public.

SHRI M. P. BHARGAVA (Uttar Pradesh): The truth would have come out in that case.

SHRI A. D. MANI: We have now got only a medium of the truth, a fraction of the truth. I would have liked the whole truth to come out as a result of such cross-examination and I am sure my hon. friend, Mr. Abdul Ghani, and his friends would have gladly faced cross-examination by the counsel of Sardar Partap Singh Kairon.

I would like to say further that I am not happy also at the demand being made by the Government of the Punjab to have the officials dealt with departmentally. The fact remains—and this fact cannot be gainsaid by anybody—that these officials were responsible for their actions because they were afraid to displease Sardar Partap Singh Kairon. We are developing a new pattern of State autonomy where officials are in mortal fear of the Ministers and Chief Ministers. How do we expect the officials not to toe the line of the Ministers who are in power, particularly when they know that if they refused to do so they must be visited with punishment? I would like Mr. Sapru's sympathies to be extended to the officials and not to Mr. Partap Singh Kairon and I personally would be happy if the officials concerned are censured and the prosecution against them dropped, because they were acting more or less as the tools of Sardar Partap Singh Kairon or his son, Sardar Surinder Singh Kairon.

The third point I would like to make is if it decided that these officials should be prosecuted, then there is no alternative left but to prosecute Sardar Partap Singh Kairon himself. It would be unfair to the official of Punjab to have them prosecuted or dealt with departmentally and to allow Sardar Partap Singh Kairon to go scot-free even with his liberty to write offensive articles in the weekly journal that he has started and trying to stage a come-back to power. I would like to say this that if it is decided that the curtain should be rung on the Kairon episode, the Congress High Command should ask Sardar Partap Singh Kairon to resign from the Vidhan Sabha of Punjab. This has not been done. I would like also all those who have been adversely commented upon by the Das Commission also to resign and I would like at some stage the Government to come forward with legislation to amend the Representation of the Peoples Act to make it obligatory for any Minister who has been the subject of adverse findings of a Commission of Enquiry to forthwith vacate his seat, because unless the Minister resigns his seat, the offence is not condoned.

There is one other point I would like to make and that is so many charge-sheets are being submitted. There is a charge-sheet against the Chief Minister of Mysore. There is a charge-sheet against the Chief Minister of Orissa and the ex-Chief Minister of Orissa. These charge-sheets have been there before the public for months. We have been told that action is going to be taken, but no action has been taken and this delay itself is causing a good deal of demoralisation to the public life of this country as it is. I would like to repeat that the Santhanam Committee was on very firm foundations when it said that if ten MLAs subscribed to a charge-sheet, that matter should be properly enquired into. I would like also the present practice of charge-sheets being scrutinised by the Congress High Command to be given up. I have great respect for the members of the Congress High Command, but

[Shri A. D. Mani.]

they are a party organisation. If a complaint is made against a Chief Minister or a charge-sheet is brought forward against a Chief Minister and submitted to the President, that charge-sheet should be sent to the Attorney-General for his opinion. It is on the basis of the findings of the Attorney-General that Government should decide to institute a Commission of Enquiry or take action under the Public Servants Enquiry Act. (*Time bell rings*). I want to finish. Thank you very much for giving me this opportunity. I would like to say this. The war against corruption must go on. It cannot end only because Sardar Partap Singh Kairon has been removed from power, but such people must have no place in the public life. If the Congress is able to ensure by their deeds a decent public life, they would have done a great service to the country.

श्री जगत नारायण (पजाब) मैडम डिप्टी चेयरमैन, मैंने बड़े ग़ौर से डा० गोपाल सिंह, डा० अनूप सिंह और श्री सप्रू साहब की तकरीर को सुना । मैं बड़े अदब के साथ अपने ट्रेजरी बैंचेंज के भाइयों की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि उन्होंने इन लोगों की तक़रीर पर औसतन अपनी सम्मति दी है और कहा है कि अच्छी तकरीर है । मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं इन तीनों भाइयों ने अपनी तकरीर से प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर पंजाब के मुंह पर चपत रसीद की है । शायद आप कहेंगे कि मैं यह बात क्यों कहता हूं ? मैं यह बात इसलिए कहता हूं कि जब दास कमीशन की रिपोर्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास पहुंची तो उन्होंने इसे होम मिनिस्टर के पास भेजी । होम मिनिस्टर साहब ने एक एलची के जरिये यह रिपोर्ट चंडीगढ़ भेजी । सरदार प्रताप सिंह कैरों ने पहला काम इस रिपोर्ट के पढ़ने के बाद जो किया वह यह था कि उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया । मगर इसके साथ ही उन्होंने अपने आदमियों को इकट्ठा करके कहा कि कांग्रेस हाई कमान को बतला दिया जाना चाहिये कि ताकत हमारे साथ है । पंजाब प्रदेश के प्रेजीडेण्ट ने भी कहा कि हमें दास कमीशन की रिपोर्ट की परवाह नहीं है और हमारी पार्टी ही पावर में रहेगी ।

श्रीमती शारदा भार्गव (राजस्थान) : क्या आपने ये बातें कैरो साहब के मुह से सुनीं ?

श्री जगत नरायण : हमने ये बातें अखबारों के जरिये मालूम कीं । तो मैं पंजाब के कांग्रेस प्रेजीडेण्ट की बात कह रहा था । तो मैं अर्ज कर रहा था कि वहां पर कुछ इस तरह की बातें कही गईं जिसकी वजह से होम मिनिस्टर को इस तरह का स्टेप लेना पड़ा । उन्होंने दास कमीशन की रिपोर्ट को प्रेस के लिए रिलीज कर दी । रिपोर्ट रिलीज करने के बाद सरदार प्रताप सिंह कैरो न सिर्फ केयर टेकर गवर्नमेंट से गये बल्कि उन्हें वहां से बिल्कुल ही हटना पड़ा । लेकिन आज जो तक़रीरें यहां पर की गई हैं वे उनके हक में जाती हैं । मैं आपकी खिदमत में यह अर्ज करना चाहता हूं कि कांग्रेस हाई कमान ने और इन लोगों ने एक करप्ट चीफ मिनिस्टर की मदद की और ऐसा करके हमारे प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर ने जो कदम उठाया था उसकी निन्दा की है और दुनिया के सामने एक मजाक बनाया है ।

DR. GOPAL SINGH: It is not correct.

श्री जगत नारायण : आपने अपने बयान में कहा है । मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं और आपने सारी बातें कहीं ।

DR. GOPAL SINGH: That is not correct. Why are you putting into my mouth what I have not said.

श्री जगत नारायण : मैं आपसे लड़ना नही चाहता हूं । मैं आपकी खिदमत में यह अर्ज करना चाहता हूं कि मैमोरियलिस्टों के बारे में यह कहा जाता है कि उन्होंने जो 22

इल्जाम लगाये थे उनमें से 7 ही साबित कर पाये और 15 साबित नहीं कर पाये । मैडम आपको सारे केस का हाल मालूम है कि यह कैसे और किस ढंग पर लड़ा गया था । मैमोरियलिस्टों ने 20 इल्जाम प्रेज़ीडेण्ट के सामने पेश किये थे । हमारे पास न कोई रिकार्ड था और न कोई चीज़ ही थी जिसके ज़रिये हम अपना केस लड़ सकते थे । सिर्फ अखबारों में जो चीज़ें छपती थीं उसी को लेकर हमने इल्ज़ाम लगाये और दे दिये । लेकिन दूसरी तरफ क्या हाल थे ? वहां पर चीफ मिनिस्टर को खुली छूट थी और वह कांग्रेस का रुपया लेकर अपना केस डिफन्ड कर रहा था । उसने अपने वकील को सरकारी फण्ड से एक मिनट का 10 रुपये के हिसाब से अपने केस को लड़ने के लिये दिया और इस तरह से अपने केस को डिफेण्ड किया । इसके बावजद भी वहां पर बहुत सी फाइलों को टैम्पर किया गया, फाइलों को बिगाड़ा गया । दास कमीशन ने भी अपने रिपोर्ट में यह कहा है कि फाइलों को टैम्पर किया गया । इस तरह की तमाम बातें हुई लेकिन इसके बावजूद भी हम 20 इल्ज़ामों में से 7 इल्ज़ामों को साबित करने में कामयाब रहे ।

हमारे भाई कह रहे हैं कि 13 इल्ज़ाम साबित नहीं हो सके और इस बारे में मेरे भाई श्री अब्दुल ग़नी जी ने उनको चैलेंज किया है और मैं भी उनको चैलेंज करता हूं क्योंकि मैमोरियलिस्टों ने जो मेमोरेंडम भेजा था उसमें मैंने भी साइन किये थे । मैं भी राष्ट्रपति जी के पास साथ गया था और राष्ट्रपति जी ने हमसे पूछा था कि क्या आप ये इल्ज़ाम साबित कर सकते हैं । हमने कहा था कि अगर हम इन इल्ज़ामों को साबित नहीं कर सकेंगे तो आपकी मरजी में जो सज़ा आये वह हमको दीजियेगा । लेकिन हमको इल्ज़ामों को साबित करने का मौका दीजिये । मैं अपने भाई जो वहां से बैठ कर कह रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि वे क्यों नहीं हमारे ऊपर मकदमा चलाते हैं ? जब से मैंने कांग्रेस छोड़ी है तबसे कैरो की सरकार ने मेरे खिलाफ 20 मुकदमे चलाये । हिन्द समाचार पर चलाये और उनमें से 16 मुकदमे लड़ कर मैं बरी हुआ हूं । बावजूद इसके कि कैरो की सरकार ने सब कुछ किया फिर भी वह मुझ पर मुकदमे साबित नहीं कर सके । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जिन 13 इल्ज़ामों को हम साबित नहीं कर सके उनके खिलाफ आप हम पर मुकदमा चलाइये और फिर देखिये कि हम एक एक करके इनको साबित करते हैं या नहीं और जो हमने चार्जेज लगाये हैं वे दुरुस्त हैं या नहीं ?

मैडम, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा था कि डाक्टर गोपाल सिंह मेरे बड़े अज़ीज़ दोस्त हैं । यह तो स्कालर आदमी हैं और यह स्कालर होने की वजह से ही नामज़द हुये हैं । मुझे हैरानी इस बात की हुई कि वे सियासत में पड़ गये और यहां मेरे अज़ीज भाई पंजहज़ारी ने उनको आगे बढ़ा दिया । पंजहज़ारी साहब मिस्टर कैरों के मुताल्लिक क्या राय रखते हैं, वह मुझे अच्छी तरह मालूम है और उन्होंने इन बेचारे डाक्टर साहब को आगे कर दिया । डाक्टर साहब, आपको सियासत का पता नहीं है ।

मेरी बहन, मैं आपसे बड़े अदब के साथ कहना चाहता हू कि आप इस कुर्सी पर विराजमान हैं, इसलिये कि महात्मा गांधी ने हिन्दुस्तान को निजात दिलाई और कांग्रेस पार्टी को मज़बूत किया । एक छोटा सा वाकया मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूं । सरदार सरदूल सिंह कवीश्वर कांग्रेस वर्किंग कमेटी में थे । उन्होंने महाराजा नाभा से कुछ रुपये लिये थे और प्रोनोट लिख कर दिया था । फिर क्या हुआ कि तीन साल बाद महाराजा ने उनसे रुपया मांगा । उस पर उन्होंने कहा कि मुझे माफ कर दो । फिर मुकदमा कोर्ट में चला और कोर्ट में जवाब दावा में सरदार सरदूल सिंह कवीश्वर ने कहा कि यह रुपया मैंने नहीं लिया है । फिर यह मामला किसी ने महात्मा गांधी के पास

[श्री जगत नारायण]

पहुंचा दिया। महात्मा गांधी ने सरदार सरदूल सिह को बुला कर कहा कि आप फौरन वर्किंग कमेटी से मुस्तैफी हो जायं, काग्रेस से मुस्तैफी हो जाये, आप ऐसा जवाब दावा दे करके काग्रेस में नही रह सकते है। बड़ी मामूली बात थी और सरदार सरदूल कवीश्वर ने कहा कि यह तो वकीलो के देखने की बात है, लेकिन महात्मा गाधी ने कहा कि नही, दस्तखत तुम्हारे ही है और तुम को मुस्तैफी होना पड़ेगा। यहा दास कमिशन के सामने 22 चार्जेज मे से 7 चार्जेज हमने साबित कर दिया और उसके बाद केन्द्रीय सरकार ने ऐक्शन लिया और मजबूर किया सरदार प्रताप सिह कैरों को कि वे मुस्तैफी हो। अब इस वक्त जो बहस हो रही है और इसका जो खास मकसद है, उस पर डिटेल मे कहने के लिये मेरे पास वक्त नही है। लेकिन इतना मैं अर्ज करूंगा कि हमारी जो चार्जशीट थी वह मुख्य मंत्री के खिलाफ थी और उसमे सिर्फ उनके रेज़िगनेशन से काम नही चलेगा। उन पर मुकदमा चलाना चाहिये। और सिर्फ जनके खिलाफ ही नही, बल्कि और जिन पाच छः आदमियो के खिलाफ चार्जशीट लगाई गई थी, उनके खिलाफ भी मुकदमा चलाना चाहिये। इस मामले को यही नही छोड़ देना चाहिये। कृष्णस्वामी जी अपनी क्या रिपोर्ट देगे, उससे हमारा कोई सरोकार नही है। हम तो यह चाहते है कि दास कमिशन की रिपोर्ट मे जिन के खिलाफ कहा गया है, उनके खिलाफ ऐक्शन ले कर के मामले को आखिर तक पहुचाना चाहिये।

मैडम, आपने मुझे इतना वक्त दिया, इसके लिये आपका बहुत बहुत शुक्रिया।

THE DEPUTY CHAIRMAN: There are still four Members to participate in the discussion Then the Minister will speak, and then the Mover will reply Mr Vajpayee.

श्री ए० बी० वाजपेयी: महोदया, भ्रष्टाचार का प्रश्न किसी पार्टी का प्रश्न नही है। देश के लोकतंत्र का भविष्य इसके साथ जुडा हुआ है कि हम शासन को भ्रष्टाचार से मुक्त रख कर चला सकते है या नही। इस बात को सभी स्वीकार करेगे कि यदि भ्रष्टाचार का निराकरण करना है तो उसका आरम्भ शिखर से होना चाहिये, चोटी से होना चाहिये। यदि मत्रियो के आचरण संदिग्ध रहेगे, तो सरकारी कर्मचारियो से, सेवाओ से इस बात की आशा नही की जा सकती कि वे अपने दायित्व के निर्वाह मे प्रामाणिकता से काम लेगे।

दास कमिशन की नियुक्ति से हमारे देश के राजनैतिक जीवन मे एक नये अध्याय का श्रीगणेश हुआ है। इससे दोनो बाते साबित हो गई। एक बात तो यह है कि उचे ऊचे पदो पर बैठे हुये व्यक्ति भी भ्रष्टाचार से मुक्त नही है और दूसरी बात यह है कि भारतीय लोकतत्र सजग है, सक्षम है। जनमत जाग्रत है, ज्वलत है और भ्रष्टाचार कोई भी करे, कितने भी ऊंचे पद पर बैठा हो, जनमत उसे क्षमा नही करेगा। जनता की अदालत उसको सजा देगी।

भ्रष्टाचार के आरोप और भी लगाये जा रहे है। उनसे किसी को घबराना नही चाहिये। उन आरोपों की जांच जरूरी है और जाच का सर्वसम्मत तरीका निकालना होगा। अनेक मुख्य मत्रियो के विरुद्ध आरोप लग रहे है, यद्यपि ऐसे मुख्य मत्री देश मे ज्यादा है जिन के विरुद्ध कोई आरोप नही है और इसलिये काग्रेस पार्टी इस प्रश्न को इस तरह से न देखे कि हम आरोप लगा कर के किसी मुख्य मत्री को गिराना चाहते है। यदि आरोपो मे दम नही है, तो फिर कोई मुख्य मंत्री गिरेगा नही। वह निष्कलंक हो कर निकलेगा। उसकी कीर्ति बढ़ेगी, और काग्रेस पार्टी की प्रतिष्ठा मे भी वृद्धि होगी। किन्तु यदि आरोपो मे सार है, किसी

का आचरण संदिग्ध है, तो उसे सजा मिलनी चाहिये। अगर मुख्य मंत्री आचरण और आदर्श नहीं रख सके, तो देश में लोकतंत्र की जड़ पर कुठाराघात होगा। सीज़र की पत्नी की तरह से मंत्रियों को भी संदेह से परे होना चाहिये। क्या कोई कह सकता है कि सरदार प्रताप सिंह कैरों का आचरण संदेह से परे था? कितने आरोप साबित हुये, कितने आरोप साबित नहीं हुये, यह प्रश्न नहीं है। लोकतंत्र में मंत्रियों के आचरण को केवल संकीर्ण, संकुचित कानून की कसौटी पर नहीं कसा जा सकता। आखिर, नैतिक मूल्य को भी ध्यान में रखना होगा। शासन में लोगों की निष्ठा बढ़ाने के लिये इस बात को भी देखना होगा कि अगर अंगलियां उठती हैं तो योग्य जांच की जाय और अगर जांच में आचरण संदेह से मुक्त हो तो उसे पद से अलग कर दिया जाय।

महोदया, यह भगवान राम का देश है, जिन्होंने एक व्यक्ति के कहने पर सीताजी को छोड़ दिया था। उस व्यक्ति ने कोई स्मरण पत्र पेश नहीं किया। भगवान राम चाहते तो उसकी आवाज को दबा सकते थे, मगर उन्होंने जो श्लोक कहा है, मैं चाहूंगा कि हमारे मंत्री महोदय उसे मंढवा कर अपने दफ्तरों में टांगे :

स्नेहं दयांच सौख्यं च
यदि वा जानकीमपि
आराधनाय लोकानाम्
मुंचतो नास्ति मे व्यथा"

मैं स्नेह को छोड़ दूंगा, दया को तिलांजलि दे दूंगा, व्यक्तिगत सुख की चिंता नहीं करूंगा, आवश्यकता पड़ी तो सीता को भी छोड़ दूंगा। "आराधनाय लोकानाम्" लोक अपवाद के डर से अग्नि परीक्षा में निष्कलंक हो कर निकलने वाली सीता को भगवान राम ने छोड़ दिया। सवाल कानून का नहीं है। सवाल इस बात का है कि हम अपने जन जीवन के सामने कौन सा आदर्श रखना चाहते हैं।

कोई इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि सरदार प्रताप सिंह कैरों के मुख्य मंत्री होने का लाभ उठाकर उनके पुत्रों ने जायदादें खड़ी कीं। कमिशन इस बात पर भी स्पष्ट है कि सरदार प्रताप सिंह कैरों को पता था, उनके ध्यान में लाया जा चुका था कि उनके लड़के उनके पद का दुरुपयोग कर के जायदाद खड़ी कर रहे हैं। वे यह कह कर नहीं बच सकते कि मेरा पुत्रों से क्या सम्बन्ध है। शासन की कुर्सी पर बैठ कर व्यक्ति को निर्मम होना होगा, कठोर होना होगा। उसे स्नेह के सम्बन्धों को तोड़ना होगा। उसे पुत्रों के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति, नातेदारों के प्रति और प्रकार का व्यवहार करना पड़ेगा। अगर हमारे मंत्री ऐसे आदर्श का पालन नहीं कर सकते, तो देश में लोकतंत्र के विकास के लिए मुझे खतरा दिखाई देता है।

इस रिपोर्ट में चार श्रेणियों के विरुद्ध अभी कार्यवाही बाकी है। एक सरदार प्रताप सिंह कैरों स्वयं, दूसरे उनके परिवार के लोग, तीसरे ऐसे गैरसरकारी लोग जिनका इस रिपोर्ट में उल्लेख है, जिनमें कुछ मंत्री भी आते हैं और जिन की ओर हमारे कुछ मित्रों ने संकेत भी किया है। कुछ सरकारी

6 P.M. अफसर जिन्होंने पद के दुरुपयोग में हिस्सा बटाया, जिन्होंने कैरों के पुत्रों को लाभ उठाने देने के लिए अनियमितताएं कीं, जो उन्हें फायदा पहुंचाने में हिस्सेदार बने, इन चारों के खिलाफ हम जानना चाहेंगे गृह मंत्रालय क्या कार्यवाही कर रहा है। मैं "विचहण्ट" का हामी नहीं हूं लेकिन अगर अपराधी को पूरी सजा नहीं मिले तो न्याय का तकाजा पूर्ण नहीं होगा। हां, जिनका नाम लिया गया है उन्हें सफाई का मौका दिया जाना चाहिए, उन पर बाकायदा आरोप लगाए जांय, सफाई का मौका दिया जाय, जांच हो और अगर जांच में साबित हो जाय कि जानबूझ कर उन्होंने पद का दुरुपयोग किया तो फिर वे दंड के

[श्री ए० ब ० वाजपेयी]

भागीदार हैं। और, जो गलत ढंग से जायदाद इकट्ठी की गई है उसका क्या होगा ? जो ब्लैकमनी कमाए हुए है उनके खिलाफ वित्त मंत्रालय कार्यवाही करना चाहता है, हम इस कार्यवाही का स्वागत करते हैं, लेकिन सत्ता का दुरुपयोग कर के जिन्हों ने पंजाब में जायदादें खड़ी की हैं वे जायदादें किस तरह से कमाई गई हैं इसकी जांच होनी चाहिए। वह अपनी सफाई दें लेकिन अगर वह साबित नहीं कर सकते कि जायदाद जायज़ तरीकों से आई है तो वह जायदाद जब्त होनी चाहिए। किसी के पीछे डंडा ले कर पड़ने की ज़रूरत नहीं है। मगर भ्रष्टाचार के मामले में किसी के साथ रियायत भी नहीं होनी चाहिए।

एक बात कह कर मैं समाप्त कर दूगा। मुख्य मंत्रियों के, मंत्रियों के विरुद्ध जो आरोप लगे हैं उन सब मे एक ही तरीका अपनाना ज़रूरी है। हम पंजाब मे कुछ करे, उड़ीसा में दूसरा ढंग अपनाएं और मैसूर के आरोपों के सम्बन्ध में अलग नीति अपनाएं इससे देश में सही वातावरण नही बनेगा। संथानम् कमेटी की सिफारिश सरकार स्वीकार करले कि एक "नैशनल पैनेल" बनेगा और अगर विधान सभा के, संसद् के, १० सदस्य राष्ट्रपति के पास आरोप लगाये तो उसे पैनेल के पास भेज दिया जाय। गृह मंत्री जी को या प्रधान मंत्री जी को यह भार अपने ऊपर नही लेना चाहिए, वे सत्तारूढ़ दल के हैं, मैं उनकी ईमानदारी पर शक नहीं करता मगर कुछ कांग्रेसी कल उनकी ईमानदारी पर शक करेगे इसमें मुझे कोई संदेह नही है, उन पर आरोप लगाएंगे कि वे गुटबन्दी के आधार पर अलग अलग ढग का व्यवहार कर रहे है, उड़ीसा के सम्बन्ध में ये अरोप लग रहे है। मैं चाहता हू कि एक समान तरीका अपनाया जाय। मेरे मित्र श्री चौरड़िया जी और मणि जी ने भी कहा कि आरोप एटार्नी जनरल को भेज दिए जाय और वह देखे कि प्राइमाफेसी केस है या नहीं और अगर है तो फिर कमिशन आफ इंक्वायरी कायम होनी चाहिए। अगर सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते तो संथानम् कमेटी की सिफारिश को मान ले कि प्रमुख व्यक्तियो का एक नैशनल पैनल बने और उनमें से दो तीन व्यक्तियों को जो आरोप लगते है उनको भेज दिया जाय। कांग्रेस के सदस्यों को इन आरोपों से भयभीत नही होना चाहिए। लोकतंत्र और भ्रष्टाचार इनमें बडा गहरा सम्बन्ध है और इसलिए भ्रष्टाचार के आरोपों के प्रति अधिक सावधान होना चाहिए। सवाल सत्तारूढ़ दल या विरोधी दल का नहीं है, दल आऐंगे चले जाएंगे, सरकारें बनेंगी बदल जायेंगी, मगर भारत में लोकतन्त्र रहेगा या नही रहेगा यह प्रश्न आज कसौटी पर कसा हुआ है और यदि हम भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए दृढ़ता से काम नही करेंगे तो आगे आने वाली संतति हमें कभी क्षमा नही करेगी।

SHRI M. P. BHARGAVA: Madam Deputy Chairman, . . .

THE DEPUTY CHAIRMAN: It is past six and still there are six speakers. Please be brief.

SHRI M. P. BHARGAVA: ....I am one of those who have always believed that corruption wherever it exists must be eradicated and should be eradicated expeditiously. We have been seeing that the plea that time is the healer of all evils has been responsible for many an awkward situation for the ruling party. Now I have been listening to the debate today and I have failed to understand what purpose the debate is going to serve. The Report of the Das Commission was submitted on the 11th June 1964. It was placed on the Table of the House on the 7th September, 1964. I was the first to give a motion for its discussion on the 8th September, 1964.

SHRI A. B. VAJPAYEE: For what purpose?

SHRI M. P. BHARGAVA: There was a purpose at that time. The Report had been submitted and the purpose

at that time would have been to impress upon the Government how action has to be taken in following up the recommendations of the Report. Now if we analyse from that angle, we find that it is too late in the day to discuss the Report from that angle.

There are five sets of people affected by the Report as was rightly pointed out by my friend, Shri Atal Behari Vajpayee. First is the Chief Minister. The Chief Minister has already given up his Chief Ministership . . .

SHRI A. B. VAJPAYEE: Is that all?

SHRI M. P. BHARGAVA: .... and other action about his Assembly seat being vacated is before the High Command, and I am sure before very long the High Command will give a decision and advise Sardar Partap Singh Kairon accordingly.

The second set of people affected by the Report are the sons and family members of Sardar Partap Singh Kairon. As far as the sons are concerned, action is being taken. Some of the cases are *sub judice* and it will be improper to discuss them here in this House. About tax evasion a special Income-tax Officer has been appointed to go into the returns of the two sons and other family members. As far as action on that count is concerned, it is in progress. The third set of people affected are the officials who are said to have connived at or helped in the activity of Sardar Partap Singh Kairon's sons. Here again action is being taken. A Special Officer, by the name, Mr. Krishnaswamy, was appointed long back. He has gone through the various papers before him. He is going through the Report and action on that count is also in progress. The four sets of people affected are the non-officials or some of the Ministers in Sardar Partap Singh Kairon's Cabinet and some other non-officials. Action against them is also being contemplated. The High Command is fully seized of the matter. On that count there can be no grievance as far as Mr. Abdul Ghani Dar and others are concerned.

Now I come to one set of people to which Mr. Vajpayee did not refer and which I have to refer very painfully. And that is the memorialists who have submitted their allegations and about whom strictures have been made in the Report. To apprise the House of the correct situation I will draw the attention of the House to some of the strictures and I will leave it to the House to draw their inference whether any action is called for or not. If any action is called for, I will implore the Home Minister to move in that matter also because justice should be done to all quarters. We cannot follow a policy of persecution or going against one man who has already been ousted from the high position he occupied and leave the other set of people, who according to the remarks of the Commission itself, are charged with bringing some frivolous charges. I quite agree that some of their charges have been substantiated and for that the people affected are paying the penalty. Now on page 266 of the report it is said:

> "On the basis of the evidence furnished by these properly verified counter-affidavits the relevant portions of which have been summarised above and which the Commission accepts as true it will be seen that . . . "—

Mark the words—

> " . . . all the major premises of Maulvi Abdul Ghani Dar's affidavit were incorrect."

That is a very sweeping remark of the Das Commission and we must take some recognition of this. Then it goes on to say:

> "The Commission is satisfied that the insistence even on this flagrantly untenable charge is indicative of only of the strained relation that exists between the Memorialists and S. Pratap Singh Kairon and which has warped . . . "—

[Shri M. P. Bhargava.]

Mark again the word—

"....their vision and vitiated their mind and faculty of reasoning. Their mental state is well explained by the following observations or. Baron Alderson in Reg. Vs. Hodge (1838) 2 Law. 227:

"The mind was apt to take a pleasure in adapting circumstances to one another, and even in straining them a little, if need be, to force them to form parts of one connected whole; and the more ingenious the mind of the individual, the more likely was it, considering such matters, to overreach and mislead itself, to supply some little link that is wanting, to take for granted some fact consistent with its previous theories and necessary to render them complete."

(Time bell rings.)

Is my time over?

THE DEPUTY CHAIRMAN: No, but I said you should take a little less than ten minutes because you have to accommodate others. I do not know how long the House is inclined to sit.

SHRI M. P. BHARGAVA: If you want me to stop I will stop here; otherwise I will require a couple of minutes. I have no time; otherwise I would have read out to the House passages after passages where strictures have been passed by the Das Commission on the memorialists. I do not say that justice should not be done against Sardar Kairon. Whatever he deserves must be given to him and I am one of those who always believed that justice should have been given to him a long time past and but for the inaction, if I may say so, of the High Command, things would not have taken all the ugly shape which they took.

Now if we go back a little, if you will allow me two minutes, this story of Das Commission's appointment is not a solitary instance. It takes us back to 1947. There was a constant fight between the 'haves' and the 'have-nots' in the Punjab Congress and fortunately or unfortunately, I have been connected with Punjab since a long time. I know from my inner knowledge all the activities of my friends who have spoken from the Opposite Benches. I am referring to Mr. Abdul Ghani and my friend Mr. Jagat Narain. When they found that they could not seize power so long as Sardar Kairon, a strong man as he was, was present on the scene, they started looking for things with which to beat Mr. Kairon, and unfortunately his sons provided them with all the material which they wanted and that is the sad story of Punjab. I am still not prepared to believe that Sardar Kairon is all that bad as he is depicted to be. He is a strong man and the whole world knows that strong men create enemies in their sphere of work and that is what has been happening and his family members and his son have provided all the gun-powder to the memorialists.

Then we have been talking about so many officials. What are the officials to do? A certain regime is in power. Certain orders are given orally. Certain orders are written. They have to execute them and be in 'pulling on' terms, if I may say so, with the authorities that are in position.

SHRI A. B. VAJPAYEE: They should have refused to submit affidavits.

SHRI M. P. BHARGAVA: Please bear with me. Everybody is not Mr. Vajpayee or Bhargava who will resist all kinds of things. Human material is human material and there are people who take every opportunity which is offered to them. I need not disclose certain other things which I know about the Opposition because it is not the time to do so. On some other occasion I shall do that also.

SHRI A. B. VAJPAYEE: Let us come to power first.

SHRI M. P. BHARGAVA: You speak about that. In the end I will only implore upon the Home Minister to make the whole thing balanced and let it not appear to the world that the High Command or the Government of India go with a prejudice against anybody and they do not take action where it is called for, they go too far where it is not required. That is all that I have to say in this regard. Thank you.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Panjhazari. Only five minutes please.

सरदार रघुवीर सिंह पंजहजारी (पंजाब): डिपुटी चेयरमैन साहिबा, मुझे खुशी होती कि जिस प्रजातंत्रवाद का नारा हमारी अपोजिशन पार्टी के मेम्बर लगाते है उसको सही मानों मे जानते होते । अगर वे दास कमीशन की रिपोर्ट पर कांग्रेस सरकार की तारीफ करते और जिस तरह दास कमीशन की रिपोर्ट पर कांग्रेस हाई कमान्ड ने स्ट्राग ऐक्शन पजाब के मुताल्लिक लिया उसकी भी तारीफ करते तो मै समझता कि सही मानों में उन्होने प्रजातंत्रवाद को मजबूत करने की कोशिश की । मुझे पटेल साहब के यह कहने से अफसोस हुआ कि हमारे पिछले प्रधान मंत्री जी ने एक राय दी थी कि सरदार प्रताप सिह कैरो बहुत स्ट्राग आदमी है, अच्छा काम करने वाला है । लेकिन वह राय बनाने वालो मे किनका ज्यादा हाथ था ? उस राय को बनाने वालो मे अगर सबसे पहला हिस्सा किसी ने लिया तो हमारे लाला जगत नारायण थे जो पंजाब पी० सी० सी० के जेनरल सेक्रेटरी थे और जो ७० एम० एल० एज० का डेपुटेशन लेकर यहा आये थे तो हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री जी से कहा था कि अगर पजाब को बचाना है तो आप को सरदार प्रताप सिह कैरो को ही मख्य मंत्री बनाना होगा ।

श्री जगत नारायण : नही, मैने नही कहा । आप गलत बात कह रहे है ।

सरदार रघुवीर सिंह पंजहजारी : उसके बाद आप उनके साथ एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे लेकिन जब . . .

हम आह भी करते है, हो जाते है बदनाम
वह कत्ल भी करते है, चर्चा नही होती ।

(Interruptions.)

सच्चर साहब के मुकाबले मे सरदार प्रताप सिह कैरो को चीफ मिनिस्टर बनाने वाले आप है, इसको आप डिनाई नही कर सकते ।

श्री जगत नारायण : मै सच्चर साहब को लेकर आया था और मैने कहा था कि उनको चीफ मिनिस्टर रहने दीजिये, उनको नही हटाइए और सरदार प्रताप सिह कैरों को चीफ मिनिस्टर न बनाइये ।

सरदार रघुवीर सिंह पंजहजारी : उसके बाद आप पंजाब मे चीफ मिनिस्टर श्री कैरों के साथ एजूकेशन मिनिस्टर भी रहे और वह जमाना इतना वर्स्ट रहा जो कि पंजाब के इतिहास मे अब तक नही रहा । और दोनो सज्जनो के होते हुए वहां पर हिन्दी और पंजाबी का झगड़ा चला । इसके बावजूद भी सरदार प्रताप सिह कैरो ने बहुत अच्छे काम किये लेकिन जब अपोजीशन वालो ने उनके खिलाफ आरोप लगाये तो हमारे प्रधान मंत्री जी ने प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए, हिन्दुस्तान की जनता और कांग्रेस के वकार को ऊंचा करने के लिए उन्होने दास कमीशन को मुकर्रर किया । जिस रोज दास कमीशन की रिपोर्ट निकली उसी रोज कांग्रेस हाई कमान्ड ने न सिर्फ सरदार प्रताप सिह कैरो को चीफ मिनिस्टर से अलग किया बल्कि उन मिनिस्टरो को भी अलग कर दिया जिनके मताल्लिक दास कमीशन ने स्लाइटली रिमार्क किये थे । मै समझता हूं कि दुनिया के अन्दर इस किस्म की मिसाल कांग्रेस सरकार के अलावा और कोई दूसरा नही दे सकता । कांग्रेस ने इस तरह की

[सरदार रघुवीर सिंह पंजहज़ारी]

कार्यवाही न सिर्फ पंजाब ही मे की बल्कि जहा कही भी अपोजीशन पार्टीज ने चीफ मिनिस्टरो या दूसरे मिनिस्टरो के खिलाफ बाते कही उनके खिलाफ प्राइम मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब ने सी० बी० आई० को केस देकर इन्क्वायरी करवाई । मैं इस हाउस को यकीन दिलाना चाहता हू कि अगर किसी काग्रेस मिनिस्टर के खिलाफ़ या किसी काग्रेसी पार्लियामेन्ट मेम्बर के खिलाफ करप्शन की कोई शिकायत होगी तो वह काग्रेस मे नही रह सकेगा, उसकी जगह दूसरी होगी । लेकिन मैं अपोजीशन पार्टी के मेम्बरो से पूछना चाहता हूं कि क्या उनका भी यही रवैया रहेगा ? नही रहेगा । पजाब के अपोजीशन पार्टी के मेम्बरो ने स्मगलरो का साथ दिया । मैं यह कहता हू कि पजाब के अपोजीशन पार्टी के मेम्बरो ने स्मगलरों को असेम्बली के टिकट के लिए उम्मीदवार बनाया ।

श्री ए० बी० वाजपेयी सरकार आपकी थी, आपने उसको पकड़ा क्यो नही ?

सरदार रघुवीर सिंह पंजहजारी : लेकिन इसके बावजूद म यह कहता हूं कि ठीक है हमारी गलती है, हम इसको मानेगे । अगर सरदार प्रताप सिंह कैरों ने कोई खराब कार्यवाही की होगी तो अदालत में उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा । अगर उनके किसी लड़के ने टैक्स नही दिया होगा तो उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा । मै यहां पर उनको डिफेन्ड करने के लिए नहीं आया हू । चार चीजों के बारे में दास कमीशन ने उनके खिलाफ़ राय दी है और उसी के मुताबिक हम ने फैसला किया ; जैसा कि मेरे दोस्त श्री भार्गव जी ने कहा कि एक अफसर वहा पर इन्क्वायरी करने के लिए गया हुआ है और अगर उनके खिलाफ़ कोई रिपोर्ट होगी तो उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जायेगी । लेकिन क्या मैं यह उम्मीद कर सकता हूं कि दास कमीशन ने श्री अब्दुल गनी के खिलाफ यह कहा था कि उन्होंने जो आरोप लगाये थे वे गलत साबित हुए, तो क्या वे इस पार्लियामेन्ट से अपनी मेम्बरी का इस्तीफा दे देंगे ? वे कभी नही देंगे बल्कि इस बात की कोशिश करेगे कि इस केश को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लाइट किया जाय ।

(Interruptions.)

شری عبدالغنی : مجھ پر مقدمہ چلائیے -

†[**श्री अब्दुल गनी** : मुझ पर मुकदमा चलाइये ।]

THE DEPUTY CHAIRMAN: Order, order.

श्री रघुवीर सिंह पंजहजारी :

हम आह भी करते है, हो जाते है बदनाम,
वह कत्ल भी करते हैं, चर्चा नही होती ।

यहा पर अपोजीशन वाले डमोक्रेसी की बात कहते है लेकिन आपने जो ज़हनियत दिखलाई है उससे मालूम हो जाता है कि आप डैमोक्रेसी को कितना चाहते है । आप पंजाब असेम्बली के अन्दर इस तरह की गालियां दे सकते है लेकिन यहा पर हिन्दुस्तान के चुने हुए आदमी आये हुए हैं ।

(Interruptions)

आप दूसरों पर आरोप तो लगाते हैं लेकिन अपना इस्तीफा नही देंगे । जैसा कि मैं अर्ज कर रहा था कि भार्गव साहब ने कहा कि वहा एक अफसर गये हैं जो इस मामले की छानबीन कर रहे हैं । अगर कोई अफसर किसी वजह से या किसी के असर से ग़लत स्टेटमेंट देता है तो वह अफसर होने के काबिल नही है । आज वह एक आदमी के असर पर इस तरह की बात करता है तो कल वह दूसरे आदमी के असर से भी ग़लत काम कर सकता है जिसकी वजह से न सिर्फ

†[ ] Hindi transliteration.

सरकार बदनाम होगी बल्कि इसका असर दूसरे अफसरों पर भी खराब पड़ेगा । इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर साहब इस तरह के अफसरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगे । वहां के अफसरों के खिलाफ जिन्होंने ग़लत काम किया है इतना स्ट्रांग ऐक्शन लेंगे ताकि हिन्दुस्तान के दूसरे अफसरों को ग़लती करने का मौका न मिले ।

شری عبدالغنی: ہم پر مقدمہ چلائیے-

†[श्री अब्दुल गनी : हम पर मुकदमा चलाइये ।]

सरदार रघुबीर सिंह पंजहजारी : इसके साथ ही साथ मैं यह भी अर्ज़ करना चाहता हूं कि आप पंजाब असेम्बली की प्रोसीडिंग्स देखिये । वहां पंजाब के अपोजीशन मेम्बरों के खिलाफ यह आरोप लगाया गया है कि वे स्मगलिंग करते रहे हैं और इस काम को करवाने में उनका हाथ रहा है । इस तरह के लोगों के खिलाफ भी ऐक्शन लिया जाना चाहिये ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं और जैसा कि अभी श्री वाजपेयी जी ने राम-राज्य के बारे में कहा था, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार हिन्दुस्तान में राम-राज्य कायम करेगी जिसमें कांग्रेस हिन्दुस्तान की जनता का सहयोग लेगी । जितनी देरी तक जनता कांग्रेस को सहयोग देती रहेगी उतनी देर तक वह राज्य करेगी । मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि आज पंजाब में जितनी भी अपोजीशन की पार्टियां हैं उन्होंने दास कमीशन की रिपोर्ट को लेकर हमारे खिलाफ एक मुत्तहदा मुहाज बोला है । लेकिन पंजाब की दोनों सीटों को आज कांग्रेस ने जीत लिया है और वहां पर जो कांग्रेस कैन्डीडेटस खड़े हुए थे वे जीत गये हैं । इसका मतलब यह हुआ कि पंजाब की जनता ने अपोजीशन पार्टियों के खिलाफ़ फैसला दिया है और कांग्रेस के हक़ में फ़ैसला दिया । इससे यह साबित हो जाता है कि कांग्रेस ही इस देश में सब से बड़ी जमात है ।

†[ ] Hindi translation.

The DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Kureel, the Minister will reply exactly at 6.30.

شری پیارے لال کریل "طالب" (اتر پردیش): میڈم ڈپٹی چیرمین- اپوزیشن پارٹی والوں نے جس کے بارے میں اپنی آواز اٹھائی تھی اور جو ان کی بات سنی گئی اس سے ان کو فخر ہونا ہی چاہئے - لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ جو برسراقتدار پارٹی ہے اس کو بھی اس بات کا فخر ہونا چاہئے کہ جمہوریت میں جو اپوزیشن کی پارٹیاں ہوتی ہیں اور ان کے جو فرائض ہوتے ہیں وہ انہوں نے اچھی طرح سے نبھائے - اپوزیشن والوں نے ایک آواز اٹھائی تھی اور اس کے ساتھ ہی جنتا کی آواز تھی - اور سب لوگ جانتے تھے کہ پنجاب میں کیا ہو رہا تھا وہاں پر ایک رین آف ٹیرر تھا یہ صرف ہمارے کہنے کی بات نہیں ہے بلکہ اس طرح کی باتیں اخباروں میں شائع ہوتی رہتی تھیں-یہ بات ٹھیک ہے کہ پنجاب نے بہت ترقی کی - انڈسٹری میں ترقی کی - اور کئی باتوں میں اس نے ترقی کی - لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگر کوئی ایک شخص کرپٹ ہوتا ہے تو اس کو جائز نا جائز طریقہ

[شری پیارے لال کریل طالب]

سے بنایا رکھا جائے - یا وہ اپنی پوزیشن کا نا جائز فائدہ اٹھائے اور اس کے خلاف کوئی کاروائی نہ ہو - میں برسراقتدار پارٹی کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے آخر میں ہمارے بات کو سنا - جنتا کی آواز کو سنا اپوزیشن کی آواز کو سنا - اور اس چیز کے لئے انہیں داس کمیشن کو مقرر کرنا پڑا -

سورگیہ پردھان منتری جی ہمارے کیروں کے بڑے حامی تھے ان کی تعریف کرتے تھے - لیکن وہ بھی آخر میں مجبور ہوئے کہ ان کے خلاف کاروائی کی جائے - میں یہ کہونگا کہ جمہوریت میں ہر آدمی کو جمہوریت کو کامیاب بنانے کے لئے ہر طرح کی کوشش کرنی چاہیئے جیسا کہ عبدالغنی جی نے کہا کہ سردار پرتاپ سنگھ کیروں کو نکالا جانا یہ ایک انہیں کی کامیابی نہیں نہ ہی کسی ایک آدمی کی کامیابی نہیں ہے بلکہ جنتا کی کامیابی ہے جمہوریت کی کامیابی ہے -

اب سوال یہ ہے کہ داس کمیشن کے بعد ہم کو کیا کرنا چاہیئے - ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا یا ایک دوسرے کی برائی کرنا ایک دوسرے سے یہ کہنا کہ بھائی غلطی ان کی تھی یا یہ کہنا کہ داس کمیشن نے اپوزیشن کے ممبروں کے بارے میں بھی کیچڑ اچھالا ہے - تو اس سے جمہوریت مضبوط نہیں ہو سکتی ہے - جیسا کہ عبدالغنی صاحب نے کہا کہ آپ ہم پر مقدمہ چلائیے - انہوں نے اپنے سینہ پر ہاتھ رکھکر کہا تھا کہ اگر میں قصوروار ہوں تو آپ میرے اوپر مقدمہ چلائیے - اس میں غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے - اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ جو باتیں کہتے ہیں شاید فیر کمپلیکس کی وجہ سے کہتے ہیں کیوں کہ یہ بات بہت سے کانگریس منسٹروں کے خلاف بھی ہونے جا رہی ہے حالانکہ اس طرح کے معاملوں کو اٹھائے بہت دیر ہو چکی ہے لیکن ہماری سرکار کو ترنت دھیان دینا چاہیئے - میں یہاں پر اڑیسہ کے پہلے کے چیف منسٹر شری بیجو پٹنائک اور بیرین مترا آندھرا کے کئی منسٹرس ہیں ان کے بارے میں کہنا چاہتاہوں-اسی طرح سے میسور کے چیف منسٹر کے خلاف وہاں کے تیس ایم - ایل - ایلز - اور ایم ایلسیز نے شکایت کی ہے - اسی طرح راجستھان کی بات ہے - تو ان سب باتوں کے بارے میں سرکار کو جانچ کرنے کے لئے ترنت کوئی قدم اٹھانا چاہیئے -

داس کمیشن نے اپنی رپورٹ پیش کی اور اس کے مطابق پنجاب کے چیف منسٹر نے اپنا استعفیٰ دے دیا - تو اس طرح سے ایک خطرہ

بہت اچھا ہے آپ نے جیتی ہیں - اس کے پیچھے شاید آپ کی خوش قسمتی رہی ہے کہ آپ نے داس کمیشن بٹھایا - ہو سکتا ہے کہ داس کمیشن نے جو اپنی رپورٹ دی اور اس پر جو آپ نے کاروائی کی اس کے پیچھے بھی آپ کی خوش قسمتی چھپی ہو - اس لئے اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ یہ ایک بڑی بری مثال قائم کریں گے - داس کمیشن کی یہ رپورٹ اور داس کمیشن کا اپوائنٹ ہونا ایک تاریخی بات ہے اور اس نے آپکا مستک اونچا کیا ہے - اس سے آپ ایک اچھے روپ میں جنتا کے سامنے آئے ہیں اور جمہوریت کا جو تقاضہ ہوتا ہے اس کو آپ نے پورا کیا ہے - اس لئے آپ اس چیز کو سمجھیں کہ داس کمیشن کی رپورٹ کے بارے میں اتنا کہنے کے باوجود بھی اگر کوئی کاروائی نہیں کرتے ہیں تو آپ جنتا کے خلاف ایک طرح سے کام کرتے ہیں اور جمہوریت کا گلہ گھونٹتے ہیں - تو یہ آپ کے انٹرسٹ میں ہے اور میں آپ سے درخواست کرونگا کہ اس کمیشن کی رپورٹ کے سلسلہ میں جو کچھ بھی آپ کر سکتے ہوں آپ کریں اور اس سے آپ کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیئے -

جہاں تک ہم اپوزیشن والوں کا تعلق ہے یا میموریلسٹ کا تعلق ہے آپ کو پوری آزادی ہے کہ آپ مقدمہ چلائیں - اگر آپ مقدمہ چلائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اور بھی بہت سے کی گھناؤنی ہو گئی کہ بہت سے منسٹروں کے خلاف اس طرح کی کاروائی کی جائے گی - اس طرح سے شاید آپ کے دل میں ایک فیر کمپلیکس آ گیا ہے اس میں غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے - ڈاکٹر گوپال سنگھ جی نے جو بات کہی میں ان کے جذبات کا احترام کرتا ہوں - لیکن ہمارے دوسرے بھائیوں نے کہا ہے اس میں غصہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے - یہ تو ہمارا فرض تھا اس فرض کو ہم نے نبھایا جو کچھ ہم کو کرنا چاہیئے تھا وہ ہم نے کیا - جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہو کر رہے گی - اور اس پر پردہ ڈالنے سے جمہوریت کا گلا گھونٹنا ہوگا - جہاں تک جنتا کی آواز کا تعلق ہے اس کی آواز سے پنجاب کے چیف منسٹر کیروں کو استعفیٰ دینا پڑا اور اپنی جگہ سے ہٹنا پڑا - اس کے بعد داس کمیشن نے جن آفیسروں کے خلاف کہا ہے کہ انہوں نے بھی ان کا ساتھ دیا تو ان کے خلاف بھی کاروائی کی جانی چاہیئے - تو میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ ہماری سرکار اس سلسلہ میں آگے کیوں نہیں قدم اٹھاتی - یہ تو آپ کے انٹرسٹ میں ہے -

جیسا پنجاب میں آپ کہتے ہیں کہ ہم نے دونوں سیٹیں جیت لیں - چشم ماروشن دل ماشاد

[شری پیارے لال کریل "طالب"]

چارجز ثابت ہو جائیں - تو آپ کو کھلی آزادی ہے - ہمارے بھارگوا صاحب نے بڑے زور سے کہا ہے کہ یہ ہونا چاہئے وہ ہونا چاہئے - پنچ ہزاری صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ کہ ایسا ہونا چاہئے ویسا ہونا چاہئے میں کہتا ہوں کہ بڑی خوشی سے آپ کو جو کچھ کرنا ہو کیجئے - جو کچھ آپ کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے - اور جو کچھ ہم کہتے ہیں وہ بھی صحیح ہو سکتا ہے - مگر جو کرپٹ آفیسرس ہیں یا دوسرے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے لاکھوں کروڑوں روپئے کی جائداد بنائی ہے - جنہوں نے گورنمنٹ کے روپیہ کا غبن کیا ہے - جنوں نے انکم ٹیکس اور سیل ٹیکس کا روپیہ غبن کیا ہے - یہ آپ کے انٹرسٹ میں ہے یہ سرکار کے انٹرسٹ میں ہے - یہ جمہوریت کے حق میں ہے کہ آپ ان خلاف مناسب کاروائی کریں - ہاں اگر ہم میں سے کوئی قصوروار ہو تو اس کے خلاف بھی کاروائی کیجئے - بڑے شوق سے آپ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے چار چیز لگائیے اور ہم کو چاہے جیل بھیجئے چاہے پھانسی پر لٹکائیے یا جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہو وہ کیجئے - اس میں ناراض ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے - لیکن جو کرپٹ لوگ ہیں ان کے خلاف ضرور کاروائی کیجئے -

میڈم - میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے دوتین منٹ کا وقت دیا -

†श्री प्यारेलालकुरील "तालिब" (उत्तर प्रदेश) : मैडम डिप्टी चेयरमैन, अपोज़ीशन पार्टी वालों ने जिसके बारे में अपनी आवाज उठाई थी और जो इनकी बात सुनी गई इससे इनको फ़ख़्र होना ही चाहिए । लेकिन इसके साथ ही साथ जो बरसरे इक्तदार पार्टी है इसको भी इस बात का फ़ख्र होना चाहिए कि जम्हूरिटात में जो अपोज़ीशन क. पार्टियां होती हैं और इनके जो फराएज़ होते हैं वे इन्होंने अच्छी तरह से निभाए । अपोज़ीशन वालों ने एक आवाज़ उठाई थी और इसके साथ ही जनता की आवाज़ थी । और सब लोग जानते थे कि पंजाब में क्या हो रहा था वहां पर एक रेन आफ टेर र था यह सिर्फ हमारे कहने की बात नहीं है । बल्कि इस तरह की बात अखबारों में शाए होती रहती थीं । यह बात ठीक है कि पंजाब तरक्की की और कई बातों में इसने तरक्की की । लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि अगर कोई एक शख्स करप्ट होता है तो उसको जायज नाजायज तरीके से बनाया रखा जाय, या वह अपनी पोजीशन का नाजाएज़ फायदा उठाये, और इसके खिलाफ कोई कार्रवाई न हो । मैं बरसरे इक्तदार पार्टी को मुबारकबाद देता हूं कि इन्होंने आखिर में हमारी बात को सुना, जनता की आवाज़ को सुना, अपोजीशन की आवाज को सुना और इस चीज के लिए इन्हें दास कमीशन को मुकर्रर करना पड़ा ।

स्वर्गीय प्रधान मंत्री हमारे कैरों के बड़े हामी थे, उनकी तारीफ करते थे, लेकिन वह भी आख़िर में मजबूर हुए कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई **की** जाये । मैं यह कहूंगा

† [ ] English translation.

कि जम्हूरियत में हर आदमी को जम्हूरियत को कामयाब बनाने के लिये हर तरह की कोशिश करनी चाहिए । जैसा कि अब्दुल ग़नी जी ने कहा कि सरदार प्रतापसिंह कैरों को निकाला जाना यह एक उन्हीं की कामयाबी नहीं थी, किसी एक आदमी की कामयाबी नहीं है, बल्कि जनता की कामयाबी है, जम्हूरियत की कामयाबी है ।

अब सवाल यह है कि दास कमीशन के बाद हमको क्या करना चाहिए । एक दूसरे पर कीचड़ उछालना या एक दूसरे की बुराई करना, एक दूसरे से यह कहना कि भाई गलती इनकी थी या यह कहना कि दास कमीशन ने अपोज़ीशन के मेम्बरों के बारे में भी कीचड़ उछाला है---तो इससे जम्हूरियत मज़बत नहीं हो सकती है । जैसा कि अब्दुल ग़नी साहब ने कहा कि आप हम पर मकदमा चलाइये, इन्होंने अपने सीने पर हाथ रख कर कहा था कि अगर मैं कसूरवार हूं तो आप मेरे ऊपर मुकदमा चलाइये, इसमें गुस्सा होने की जरूरत नहीं है । इससे तो यह जाहिर होता है कि आप जो बातें कहते हैं शायद फैअर काम्पलेक्स की वजह से कहते हैं क्योंकि यह बात बहुत से कांग्रेस मिनिस्टरों के ख़िलाफ़ भी होने जा रही है । हालांकि इस तरह के मामलों को उठाये बहुत देर हो चुकी है लेकिन हमारी सरकार को तुरन्त ध्यान देना चाहिए । मैं यहां पर उड़ीसा के पहले के चीफ मिनिस्टर श्री बीजू पटनायक और बीरेन मित्रा, आंध्र के कई मिनिस्टर्स हैं, इनके बारे में कहना चाहता हूं । इसी तरह से मैसूर के चीफ मिनिस्टर के ख़िलाफ़ वहां के तीस एम० एल० एज० और एम० एल० सीज० ने शिकायत की है । इसी तरह राजस्थान की बात है । तो इन सब बातों के बारे में सरकार को जांच करने के लिये तुरन्त कोई कदम उठाना चाहिए ।

दास कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश की और इसके मुताबिक पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने अपना इस्तीफा दे दिया । तो इस तरह से एक खतरे की घंटी हो गई कि बहुत से मिनिस्टरों के ख़िलाफ़ इस तरह की कार्रवाई की जायेगी । इस तरह से शायद आपके दिल में एक फैअर काम्पलेक्स आ गया है, इसमें गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है । डाक्टर गोपाल सिंह जी ने जो बात कही, मैं उनके जज़बात का एतराम करता हूं । लेकिन हमारे दूसरे भाइयों ने कहा है इसमें गुस्से की कोई ज़रूरत नहीं है । यह तो हमारा फर्ज़ था । इस फर्ज़ को हमने निभाया जो कुछ हमको करना चाहिए था वह हमने किया । जो हकीकत है वह हकीकत होकर रहेगी और इस पर पर्दा डालने से जम्हूरियत का गला घोटना होगा । जहां तक जनता की आवाज का ताल्लुक है, उसकी आवाज़ से पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैरों को इस्तीफा देना पड़ा और अपनी जगह से हटना पड़ा । इसके बाद दास कमीशन ने जिन आफ़िसरों के ख़िलाफ़ कहा है कि इन्होंने भी उनका साथ दिया तो उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जानी चाहिए । तो मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि हमारी सरकार इस सिलसिले में आगे क्यों नहीं कदम उठाती । यह तो आपके इन्टरेस्ट में है ।

जैसा पंजाब में आप कहते हैं कि हमने दोनों सीटें जीत लीं । चश्मे मा रोशन, दिले मा शाद ।। बहुत अच्छा है आपने जीती हैं । इसके पीछे शायद आपकी खुशकिस्मती रही कि आपने दास कमीशन बिठाया । हो सकता है कि दास कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट दी और इस पर जो आपने कार्रवाई की इसके पीछे भी आप की यह खुश-किस्मती छिपी हो । इसलिये अगर आप ऐसा नहीं करगे तो आप यह एक बड़ी बुरी मिसाल कायम करेंगे । दास कमीशन की यह रिपोर्ट और दास कमीशन का एप्वाइंट होना एक तारीख़ी बात है और इसने आपका मस्तिष्क ऊंचा किया है । इससे आप एक अच्छे रूप में जनता के सामने आए हैं और जम्हूरियत का

[श्री प्यारे लाल कुरील 'तालिब']

जो तकाज़ा होता है उसको आपने पूरा किया है । इसलिये आप इस चीज को समझे कि दास कमीशन की रिपोर्ट के बारे मे इतना कहने के बावजूद भी अगर कोई कार्रवाई नही करते है तो आप जनता के खिलाफ़ एक तरह से काम करते है और जम्हूरियत का गला घोटते है । तो यह आप के इन्टरेस्ट में है और मै आप से दरख्वास्त करूंगा कि इस कमीशन की रिपोर्ट के सिलसिले मे जो कुछ भी आप कर सकते हो आप करे और इससे आप को पीछे नही हटना चाहिए ।

जहां तक हम अपोजीशन वालो का ताल्लुक है या मेमोरियलिस्ट का ताल्लुक है आपको पूरी आज़ादी है कि आप मुकदमा चलाएं । अगर आप मुकदमा चलाएगे तो हो सकता है कि और भी बहुत से चार्जिज साबित हो जाय तो आप को खुली आज़ादी है । हमारे भार्गव साहब ने बडे जोर से कहा है कि यह होना चाहिए वह होना चाहिए । पंजहजारी साहब ने भी यह कहा है कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए । मै कहता हूं कि बडी खुशी से आप जो कुछ करना हो कीजिए । जो कुछ आप कहते है वह भी ठीक हो सकता है और जो कुछ हम कहते है वह भी सही हो सकता है । मगर जो करप्ट आफीसर्स है या दूसरे ऐसे लोग है जिन्होने लाखो करोड़ो रुपये की जायदाद बनाई है जिन्होने गवर्नमेंट के रुपये का गबन किया है जिन्होने इन्कम टैक्स और सेल टैक्स का रुपया गबन किया है यह आपके इन्टरेस्ट में है यह सरकार के इन्टरेस्ट मे है । यह जम्हूरियत के हक मे है कि आप इनके खिलाफ मुनासिब कार्रवाई करें । हा अगर हम में से कोई कसूरवार हो तो इसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई कीजिए । बडे शोक से आप अदालत का दरवाजा खटखटाइये चार्जिज लगाइये और हम को चाहे जेल भेजिए चाहे फासी पर लटकाइये या जो कुछ भी करना चाहते हो वह कीजिए । इसमें नाराज़ होने की कोई जरूरत नही है । लेकिन जो करप्ट लोग है उनके ख़िलाफ जरूर कार्रवाई कीजिए ।

मैडम मै आपका शुक्रिया अदा करता हू कि आपने मुझे दो तीन मिनिट का वक्त दिया ।]

THE DEPUTY CHARIMAN: Mr. Kurnool, that will do. Now, Mr. Ram Sahai, you can take your three minutes.

श्री राम सहाय : उपसभापति महोदया मुझे यह देख कर हैरत होती है कि इस हाउस मे ऐसे लोग जिनके चरित्र के बारे मे आम तौर पर और खास तौर पर दास कमीशन से शंकाएं पैदा की गई हैं वह लोग कांग्रेस को उपदेश दे रहे है । मुझे तो यह कहना है कि वे लोग सिर्फ बोलना और उपदेश देना जानते है । श्री वाजपेयी जी ने अभी बहुत अच्छे अच्छे सिद्धात इस हाउस के सामने रखे । लेकिन मैं उनसे यह पूछना चाहूंगा कि दर-असल उन सिद्धान्तों पर अमल कौन करता है ? वास्तव मे कांग्रेस पार्टी ही उन सिद्धान्तों पर अमल करती है । (*Interruptions*). उनको हमारा शुक्रगुज़ार होना चाहिये । स्वर्गीय पंडित नेहरू जो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे उनसे मैने इसी सम्बन्ध मे यह प्रश्न पूछा था कि क्या प्राइम मिनिस्टर को किसी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कोई ऐक्शन लेने का अधिकार है ? उस पर उन्होने स्पष्ट यह कहा था कि कोई अधिकार नही है । बावजूद यह कहने के उन्होने दास कमीशन को मुकर्रर किया । इस लिये बजाय इसके कि उनके बारे में अच्छे ख्यालात जाहिर किये जाते हमने यह देखा कि विरोधी पार्टियों की ओर से इस बारे मे बहुत कीचड़ उछाला गया ।

मै मिस्टर कैरो को सन् 1947 से जानता हूं । उस समय सरदार पटेल के ज़माने मे वे भी आल इण्डिया काग्रेस पार्टी कमेटी मे थे और मै भी आल इण्डिया कांग्रेस कमेटी मे था । तब से मैं उनको जानता हू और मैंने

कभी उनमें ऐसी बात नहीं देखी । उनके लड़के कैसे हैं या उन लड़कों के बारे में जो कुछ कहा गया है उसके सम्बन्ध में मुझे कुछ नहीं कहना है । लेकिन जिस तरह वहां सरदार प्रताप सिंह कैरो के ज़माने में काम हुआ जिस तरह से वहां इण्डस्ट्रीज डेवलैप हुई हैं वहां पता नहीं कितने लोगों के पुत्रों ने पैसा कमाया है । मैं यह नहीं कहता कि दास कमीशन की रिपोर्ट में जो है उसको मान्यता न दी जाय । उसको मान्यता देने के बाद ही कांग्रेस हाई कमान ने उस पर ऐक्शन लिया । वैसे मेरा तो हमेशा यह खयाल रहा है कि हमारे जजेज़ भी ह्यमेन वीकनेसेज़ से खाली नहीं हैं और इस रिपोर्ट में भी वह कमजोरी किसी न किसी रूप में प्रगट होती है । यही नहीं जितनी भी रिपोर्ट्स् हैं उन सब रिपोर्ट्स को देखने के बाद आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि उनमे निश्चय ही इस प्रकार की कमज़ोरियां रहती हैं । लेकिन फिर भी हमारे पास कोई ऐसा दूसरा साधन नहीं है जिससे हम इस प्रकार की इनक्वायरी करा सकें । बावजूद उन कमजोरियों के हम इस प्रकार के कमीशन बनाते हैं और जो उनकी रिपोर्ट होती है उस पर हम अमल करते हैं ।

इसलिये डेमोक्रेसी के सिद्धान्त का कांग्रेस को किसी और पार्टी से नहीं सीखना है । मैं यह निवेदन करूंगा कि वे केवल ज़बानी जमा खर्च करते हैं । इसलिये यदि वे कांग्रेस हाई कमाण्ड के अमल को देख करके अपना मुनासिब रवैया बदलेंगे तो वे देश का उपकार करेंगे ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, Mr. Hathi.

SHRI LOKANATH MISRA: I want to ask the. . . .

THE DEPUTY CHAIRMAN: You want to make a speech?

SHRI LOKANATH MISRA: No, Madam. I only want to put one question, since I did not have an opportunity to speak.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I hope it will be brief. What is your question?

SHRI LOKANATH MISRA: It is reported that crores of rupees in the shape of legal fees for the defence of Sardar Pratap Singh Kairon before the Das Commission were spent from the public exchequer either by the Central Government or by the Punjab Government. Is that report correct? If something has been spent, then what is the amount spent by the Punjab Government and what is the amount spent by the Government of India? We would like to know that because it is very relevant in connection with the Das Commission's Report.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI JAISUKHLAL HATHI): Madam, we are discussing the Report of the Das Commission and it will be my endeavour to deal with this subject collectively and I would not keep or have any particular case in mind. What we have discussed and the suggestions which several Members have made, these so far as the future guidance is concerned, I will take into consideration. But for the first few minutes the atmosphere was surcharged with sentiment. I am happy that Prof. Lal set the tone in order and he was followed by others also, Shri Gopal Singh and others. But that reminds me of the tense atmosphere that must have been prevailing at the time the Commission was functioning and I should like to pay a tribute to the Commission for the excellent work thy have don. To quote it in their own words:

"The Commission has received numerous petitions and letters—many of them signed and others anonymous. Some of them have freely animadverted upon its constitution and even doubted its independence and impartiality and

[Shri Jaisukhlal Hathi.]

inadequacy of its terms of reference Some have thought fit to press upon the Commission its duty to save the State of the Punjab from the imminent ruin slowly but surely brought about by what they call "the misdeeds, the blatant acts of corruption and the gross misrule" of the present Chief Minister and to serve that end to discard all legalistic approach to the problem which, according to them, is not a legal but a political one calling for a drastic remedy. These writers have also ominously hinted that the Commission will be answerable, in case it did not act up to their advice, for the bloody revolution that must inevitably follow. The rest of the correspondents have sought to impress upon the Commission the absolute indispensibility of the continued leadership of the present Chief Minister for the urgent and imperative need for protecting and furthering the best interests of all sections of the people".

In spite of the pressures, letters, applications and all that, the Commission has done a good job and we should all, at least I, express gratitude for the Report which has been produced.

Much has been said about corruption and about the duty of the Government. If the Government has done this, it is because Government thinks that there should be neat, pure administration but whatever it is, whatever it does, it does to achieve noble ends through noble means. It is not for the sake of popularity that the Government has taken this action. It is purely from this point of view that the Congress Government took this action of appointing this Commission of Enquiry, only for the purpose of arriving at the truth. After arriving at the truth, Government has also been taking action and will take action. It is not that the Commission was appointed because of any pressure from outside; it is not also that if any action is to be taken, it would be taken because of pressure from outside. It is inherent in a Government, for running it efficiently and for seeing that the tone of the administration is maintained at a high level, for seeing that people repose confidence in the Government. If they discover a wrong, it should be remedied. From this objective Government appointed this Commission and I am glad that Members opposite have also appreciated this stand of the Government but then they have a complaint to make. Their complaint is, after saying and doing all this, what is the action that Government has taken on this?

In the first instance, I think, Shri Sapru's remarks are very pertinent. We are having a Constitution of a federal type. It is because there is the Congress Party running the Governments in all the States that we can ask a Minister to resign and quit but then, if there is some other Party in power in some States and if the Ministers are elected by that Party, what would happen? Of course, if we can appoint a Commission, find him guilty and then ask him to go, it is a different matter but even then it is doubtful whether we can appoint a Commission. We thought that we need not stick to these legal technicalities. We had the power under section 3 of the Act and because we took this to be a matter of public importance, we appointed the Commission. It is a matter of public importance because a section of the people complained against a Chief Minister of the State and therefore the Government of India took the view that it was a matter of public importance. Let us now see when the Report was submitted and how much time was taken to take action so that we can find out whether there is reason for the complaint that Government was slow in taking action. The Commission was appointed on 1st November 1963 and its first sitting was held on the 23rd November, 1963. It submitted its Report on the 11th June, 1964. and the Chief Minis-

ter and the others resigned on the 14th June, 1964. This means only three days after the submission of the Report. I think this very fact should be a sufficient evidence to show that the Government meant business, that the Commission was not appointed merely as an eyewash but that the Commission was appointed for the purpose of arriving at the truth and if anything was found missing then that had to be made up and action followed sincerely and earnestly.

There were some Ministers against whom there were charges but, as Shri Vajpayee said, Ministers must set high standards. It is not necessary for them to be actually booked as offenders or guilty persons. He quoted the instance of Ramachandraji, a mere talk in the town induced him to send away Sita. I wonder whether there were any opposition parties then or whether there were politics of this nature at that time but anyway there is no doubt about the fact that the standard we want to set is of -this ordre. Mem bers on this side are definite on this point. What we want to set is a high moral standard. At the same time, we have to see things in balance. Let us not act with vengeance. If a man is guilty, he should be punished, there is no doubt about it but it should be according to the process of law. It cannot be against the procedure of law, the process of law.

Now, Shri Chordia complained that the Central Government was showing its hand towards the Punjab Government while the Punjab Government was showing the hand towards the Centre. He also asked about tax evasion, violation of the Company law and so on. If the houses of film stars could be raided, he asked why the houses of those people could not be raided. Let us understand the constitutional position. The Special Officer has been appointed by the Punjab Government. We have only loaned his services. He is looking into the cases. Let us see the time taken. As I mentioned, the Report was submitted on the 11th June, 1964. Today we are in December and hardly six months have elapsed since the Report was published. In the meantime, action has been taken against people who were directly involved. Shri Chordia's specific question was about the action to be taken by the Central Government. Now, the Central Government will come in only where Central laws are concerned, where there are breaches of Central laws. We must understand this constitutional position also. So far as the State laws are concerned, whether they be civil, criminal or revenue, it is for the State Government to take action against the persons involved, persons who have violated the laws. When a question of breach of Central laws comes up, it would be for the Centre to take action. Let us not mix up the two questions of political action and action at law. Political action is something different and it will have to be taken by the organisation. I do not want to refer to the Congress Party or the action that it would like to take. I am talking of the Central laws of which there is alleged to be a breach by Shri Pratap Singh Kairon, his sons or his relations. After going through the Report, we have already appointed a Special Income-Tax Officer in charge of Amritsar Circle and he is examining the cases of evasion of Income-Tax, etc. Now, we will have also to give some time to the officer concerned. You cannot do the thing within a month or so because various records will have to be examined, various cases have to be examined, evasion of taxes has to be examined. What I mean to say is that so far as the Central Government is concerned, an officer of the Finance Ministry—he is not Shri Krishnaswami, but a special Income-tax Officer—is looking into the income-tax evasion cases; he is also looking into cases of breaches of the company law and such other things, whatever evasion of Central laws there is. Therefore, this can be divided into distinct parts. One is cases against

[Shri Jaisukhlal Hathi.]

officers who are directly connected or mentioned in the Report as such; then there are the cases of those who are not mentioned in the Report but against whom action may be taken and thirdly the case of Sardar Partap Singh Kairon against whom political action can be taken. Then there are cases of non-officials, Ministers and others, against whom action can be taken under the laws whether the Central laws or the State laws. So far as the State laws are concerned, the Cheif Minister has made a statement in the State Legislative Assembly that civil and criminal prosecution will be launched against those against whom cases are found to be sustainable in courts of law. So far as political action is concerned, it is for the political organisation. So far as civil and criminal laws are concerned, there is no distinction whether he is a non-official or a Minister or an official. In this case the only distinction will be the State and the Central legislation.

There is the question of studying the various connected files and finding out whether an offence has been committed or not because it should not again be that people are prosecuted merely on hearsay evidence. Each case will have to be examined carefully and therefore the Punjab Government has approached us to lend the services of an officer who can look into the cases, criminal or civil, and see whether they are sustainable in court of law and to determine what should be the method. A Committee consisting of a retired High Court Judge, an administrator and their own officer is being set up and this Committee again will look into all the complicated cases and action will be taken according to that. Therefore let that impression not be created—which is sought to be created—that the Government is not taking action and this is all going to be hushed up. There is no question of anything being hushed up. If the Government wanted to hush it up, it could have hushed it up even before appointing the Commission or even after appointing the Commission it could have been hushed up. But far from it; there is no question of hushing anything up. Whatever has to be done will be done but done only with a view to achieving the ends of justice and not with a view to wreaking vengeance on anybody.

Sometimes it so happens that in our emotion we do some dis-service rather than serve the country. I do not want to give any instance and I am not going to quote from anything said here. But there is one thing which I read elsewhere, not here, about our defence efforts during the emergency. There was a charge that all the gold with which the late Prime Minister was weighed was smuggled gold. Now, as Shri Mukut Behari Lal rightly complimented and congratulated the people of Punjab, it was the national zeal, the national spirit in the people of Punjab—and Mr. Kairon is a man from Punjab; no doubt about it—that they contributed so much for defence effort during the national emergency and weighed the Prime Minister in gold. A charge was made that. . . . . .

PROF. M. B. LAL: I did not talk at all about gold.

SHRI JAISUKHLAL HATHI: I do not mean you; I am complimenting you. What I say is, an allegation was made that the recent weighing of the late Prime Minister Nehru in gold was only a ruse to maintain his own cheap popularity and to show that he is instrumental in contributing enormously to the defence effort during the emergency whereas it was all smuggled gold being convertd into white. Now, the Commission has held that there is no evidence.

SHRI AWADHESHWAR PRASAD SINHA: Which Commission? Please read it.

SHRI JAISUKHLAL HATHI: I only want to say that while Shri Mukut Behari Lal rightly compli-

mented the people of the Punjab for their national zeal and the national spirit, let an impression not go that they have no national spirit and that the weighing was done to convert the smuggled gold and that it was not contributed by the people of the Punjab Such an allegation will be detracting from the impression on which Shri Mukut Behari Lal wanted to create So, I say this is not a very happy situation After all if we have something against a person, let us say it plainly Let us call a spade a spade but let us not cast reflection on the efforts of our people who have the interests of the country at heart, our people who tried their best to contribute their everything for the defence effort, the people by whose efforts—the efforts of the national-spirited Indian Punjabis—we could get so much gold Let it not be said that it was smuggled gold That is all I say

DR ANUP SINGH I request the hon Minister to kindly quote a few words of the Das Commission had to say about this smuggled gold because it is very serious If you like, I have the quotation here

SHRI JAISUKHLAL HATHI I have the quotation here I did not want to name any individual This is what is said here by the Commission

> "There is no evidence whatever, beyond the bald assertion of Shri Ajit Kumar and Shri Jagan Nath, that the late Prime Minister had been weighed in smuggled gold"

What I wanted to say is, while emotions rise, while we have bitterness against a person, it is very likely that we make charges and allegations against him. But these charges and allegations have now been ultimately looked into by the Das Commission and they have said how far those charges are correct and how far those charges are not correct. So far as they are correct, I have already said that action is being taken and action will be taken. I would like to assure this House, let them not go with an impression that the Government is not taking any action or that it is not likely to take any action or that it is not inclined to take action We want to take action because we want to set an example that whoever does a wrong will be punished We want also to set the example that in the Administration, in the Government, the higher the position a man occupies the higher should be his moral standard That is what we want to establish Therefore, let it not be said that the Government is delaying things Madam, on 21st June the Report is published and within six months action has been taken in certain respects and we have appointed a special officer who is looking into the voluminous files and many cases have been filed with the police Six cases have already been registered; I did not want to mention it because they are *sub judice*. So, it does not mean that nothing has been done Action will be taken, that is what I want to say.

In the end, Mr Misra—he is not here now—asked a question Again it is a constitutional question Let us understand the constitutional position clearly, let us understand the implication of anything that we say or that we do The question was how much money was paid from the Punjab Treasury for the defence of Sardar Partap Singh Kairon, whether the Central Government paid it or the State Government So far as the Central Government is concerned, we have not paid anything and there is no question of our paying anything. The section question was whether it was paid by the State Government, it was paid by them Now, whether this is legal or not is a question to be examined, but there may be two views about it What view would prevail is a matter for legal experts So far as we are concerned, we are only getting it examined because I will not say any definite opinion as to whether it is right or wrong There may may be two views about it That is a matter for consideration.

7 P.M

[Shri Jaisukhlal Hathi.]

Then, there were certain remarks about the Santhanam Committee's panel and other Ministers. I think they are not relevant to the issue, but I may say that so far as the Santhanam Committee's recommendations are concerned, we have already said that if there is any case against a Central, Union Minister, or a Chief Minister, the Prime Minister will look into it. When it is a case against the Minister of a State, then the Home Minister and the Chief Minister will look into it. Where there is a *prima facie* case established, then the standards of Shri Vajpayee and Shri Mukut Bihari Lal should be observed, but at least there should be a *prima facie* case. Somebody must be satisfied. Unless that is done, it would not be proper.

Then, Madam, I would like to refer lastly to one point. Shri Abdul Ghani Dhar referred to officers. About Shri R. P. Kapur's case very often he has asked and he has been asking about it today also. He said something about the malicious prosecutions. I want to make one point clear here and that is this. If we want to function as a democracy, Parties may change, but the officers are going to remain. They are the permanent apparatus through whom we have to rule or administer. Now, they should be given certain protection. I am perfectly clear about it. There should not be any feeling among the officers that because they did a certain thing at the instance of certain person when he was in power, they are being victimised. That should not be so. I want to make it very clear. There are the cases of two officers to whom Shri Abdul Ghani Dhar has been referring very often and also during the Question Hour. The Das Commission has very clearly said that there is no case of malicious prosecution. That is a matter that I would like to clear because otherwise it would have a very demoralising effect on the officers. Of course, if they are wrong, if the yare corrupt, if they have done any illegal act, they will have to be punished. But they should not be taken to task merely if they have functioned in the normal way, in the normal routine. Secondly, it should not be open to them or the officers to say that because the Ministry changes, the other Ministry or persons in charge had done something merely because of ill-will or have done malicious prosecution. Here the Das Commission's report is that the allegations of enmity between S. Partap Singh Kairon and Shri R. P. Kapur for the two reasons mentioned by him are entirely baseless. That, on the available evidence, Shri R. P. Kapur was not arrested as a result of the enmity so alleged. That, there is no dependable evidence to hold that Shri R. P. Kapur was falsely implicated by S. Partap Singh Kairon in any of the cases, namely, M. L. Sethi's case, Dhingra's case, Ayurvedic case, Cold Storage case and the other cases. So, what I want to submit to the House is this and I am very clear about it. So far as Government servants are concerned, they should not be made handles or tools and they should not be allowed to suffer or should not be victims. At the same time, if they have done anything wrong, then they have to be punished, but that should be, again, independently.

As I said, we have to achieve an object, achieve an end, but that end has to be achieved, a noble thing by noble means and not by ignoble means, not by a spirit of vengeance but by a spirit of justice, a spirit of fairness, a spirit of humanity. Let us, therefore, view this Report from that perspective. Let us see what lessons we can learn for the future. Let us see how we can rectify the errors that have been committed, if at all they have been committed, in future, how we can guard against these errors in future, how we can allow democracy to function in a way that will bring good name to the country, a fair name to the country and good Government to the people of the country.

Thank you, Madam.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Chordia, do you want to say anything?

SHRI V. M. CHORDIA: No, Madam.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The Secretary will read a Message.

MESSAGE FROM THE LOK SABHA

THE COMPANIES (SECOND AMENDMENT) BILL, 1964

SECRETARY: Madam, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha, signed by the Secretary of the Lok Sabha:—

"I am directed to inform Rajya Sabha that Lok Sabha, at its sitting held on Monday, the 21st December, 1964, adopted the annexed motion in regard to the Companies (Second Amendment) Bill, 1964.

2. I am to request that the concurrence of Rajya Sabha in the said motion, and also the names of the members of Rajya Sabha appointed to the Joint Committee, may be communicated to this House."

MOTION

"That the Bill further to amend the Companies Act, 1956, be referred to a Joint Committee of the Houses consisting of 45 members, 30 from this House, namely:—

(1) Shri S. V. Krishnamoorthy Rao
(2) Seth Achal Singh.
(3) Shri A. Shankar Alva
(4) Shri Ramchandra Vithal Bade
(5) Shri Rajendranath Barua
(6) Shri Bali Ram Bhagat
(7) Shri Dinen Bhattacharya
(8) Shri N. C. Chatterjee
(9) Shri Sachindra Chaudhuri
(10) Shri N. Dandekar
(11) Raja P. C. Deo Bhanj
(12) Shri Bhaskar Narayan Dighe
(13) Shri G. N. Dixit
(14) Shri Gajraj Singh Rao
(15) Shri Prabhu Dayal Himatsingka
(16) Shri Cherian J. Kappen
(17) Shri R. N. Yadav Lonikar
(18) Shri Madhu Limaye
(19) Shri Ghanshyamlal Oza
(20) Shri Shivram Rango Rane
(21) Shri J. Ramapathi Rao
(22) Shri R. V. Reddiar
(23) Shri Era Sezhiyan
(24) Swami Ramanand Shastri
(25) Shri Digvijaya Narain Singh
(26) Shri Sivamurthi Swami
(27) Shri Radhelal Vyas
(28) Shri K. K. Warior
(29) Shri Nagendra Prasad Yadav and
(30) Shri T. T. Krishnamachari.

and 15 from Rajya Sabha;

that in order to constitute a sitting of the Joint Committee the quorum shall be one-third of the total number of members of the Joint Committee;

that the Committee shall make a report to this House by the last day of the first week of the next session

that in other respects the Rules of Procedure of this House relating to Parliamentary Committees shall apply with such variations and modifications as the Speaker may make and

that this House recommends to Rajya Sabha that Rajya Sabha do join the said Joint Committee and communicate to this House the names of 15 members to be appointed by Rajya Sabha to the Joint Committee."

THE DEPUTY CHAIRMAN: The House stands adjourned till 11 A.M. tomorrow.

The House then adjourned at six minutes past seven of the clock till eleven of the clock on Tuesday, the 22nd December, 1964.

GMGIPND—RS—1134 *l*—1-5-65—560.